हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 मार्च, 1979

खण्ड 1 अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 20 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)24
ध्यानाकर्शण सूचनाः–	
बाद ाहपुर और उमरी (कुरूक्षेत्र) मैं भाराब के ठेकों की नीलामी सम्बन्धी	(11)29
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(11)30
वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)	
परि ाश्ट	(i)

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 20 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक , हरियाणा सभा हाल , विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होगें।

Chaupals for Harijans

***1150. Ch. Bhagmal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total numbe of chaupals for Harijans constructed during the year 1978-79 (upto 28-2-79);

(b) the total number of chaupals which are under construction at present;

(c) the total amount which has been spent by the Government on the construction of chaupals as referred to in part(a) above;

(d) the total amount likely to be spent by the Government on the chaupals as refrerred in part (b) above; and

(e) whether the unspent amount out of the amount earmarked for the construction of chaupals for the year 1978-79 be spent by 31-3-79?

श्री अध्यक्षः इस प्र न के उत्तर के लिए गवर्नमैंट ने ऐक्सटेन्शन मांगी थी जो ग्रान्ट कर दी गई है। इस बारे में सम्बन्धित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार हैः—

"Prit Singh"

Do. No. 3/12/78-SW(4)

Revenue Minister,

Haryana, Chandigarh.

Dated 17/19th March, 1979.

Subject:- Starred A/Q No. 1150 asked by Sh. Bhagmal, M.L.A. regarding Chaupals for Harijans.

Dear Col. Sahib,

I write to inform you that Starred Assembly Question No. 1150, to be asked by Shri Bhagmal, M.L.A. was received in the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department on 13-3-79. The required information is being collected. I, however, feel that it would not be4 possible

to collect the information asked for within the short period to answer the question on 20th March, 1979.

2. I would, therefore, be grateful if you could kindly allow extension of one month and fix another date for answering this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Prit Singh)

Col. Rao Ram Singh

Haryana Vidhan Sabha.

तारांकित प्र न सं0 1152

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्या, श्रीमती सुशमा स्वराज, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थी।

Disparity in the pay scales of work charged employees

***1162. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the time by which the difference in the pay scales of the work charged employees and regular employees working in the Irrigation Department will be removed; and

(b) whether the uniform and cycle allowance will be given to the work charged and Class IV regular employees of the above said Department?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): (क) सिंचाई विभाग व अन्य लोक निर्माण भाखाओं केक नियमित व वर्कचार्ज्ड कमर्चारियों के वेतनमानों का सं ोधन करना सरकार के विचारधनी है, इसलिये इस बारे में समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

(ख) चतूर्थ श्रेणी के सभी नियमित कर्मचारियों को सईकल भत्ता व वर्दियां दी जा रही है। जहां तक वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों का सम्बन्ध है यह विशय सरकार के विचाराधीन है। इस के साथ–साथ स्पीकर साहब, वर्कचार्ज्ड कर्मचारियों के मुताल्लिक अपनी बजट स्पीच में वित्त मंत्र, श्री मूलचन्द जैन जी ने भायद कुछ कहा था। हम ने तो केस फाइनैंस डिपार्टमेंट को भेज दिया था। यदि उन्होने कोई फैसला किया हो तो वे बता सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): स्पीकर साहब, वर्कचार्ज्ड ऐम्पलाइज के बारे मे हमने बजट में अनाउंसमैंट की है और उन की लगभग सारी की सारी मांगे पूरी कर दी है। इससे कोई लगभग 24 लाख रूपये सालाना वेजिज के कारण सरकार पर खर्चा बढ़ा है।

श्री अध्यक्षः आपका मतलब है कि यूनीफार्म और साईकिल अलांउस भी इसमें भामिल है?

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि यह उसमें भामिल नहीं है।

स्वामी अग्निवे ानः आदरणीय स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर आज जो दैनिक वर्कचार्ज्ड मजदूर काम करते है, उनका न्यूनतम वेतन 7 रूपये रोजाना है लेकिन उनको 7 रूपये रोज नहीं मिल रहे है बल्कि उनको 6 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहे है। चाहिये तो यह था कि उनकी इस 7 रूपये की रा ि ा को बढाकर 12 रूपये कर दिया जाता। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेगें कि आया सरकार वर्क चार्ज्ड गरीब मजदूरों के देनिक वेतन को 7 रूपये से बढ़ा कर 12 रूपये करने का विचार रखती है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अभी सरकार इस किस्म का कोई विचार नहीं कर रही है।

Appointment of Pay Commission

***1120. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Finance be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to associate any member of the Haryana Vidhan Sabha with the Pay Commission appointed by the State Government to revise and to remove

the anomalies in the pay scales of the Haryana Government employees in different Departments; and

(b) if reply to part (a) above be in the positive, the time by which the said proposal is likely to be materialized?

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन):

(क)जी नही।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि पे–कम ीन अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा और क्या सरकार की तरफ सें कोई हिदायत जारी की गई है कि वह अपनी रिपोर्ट इस निर्धारित तिथि तक दे दे?

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से पे–कमी ान को यह कहा गया है कि वह क्लास 3 और क्लास 4 के बारे में अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर–अन्दर और मुकम्मल रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर–2 दे दे।

Reduction in bus fare

***920. Swami Adityavesh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the bus fare and freight in the State?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला): नहीं।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, अभी–2 मंत्री महोदय ने मेरे प्र न के उत्तर में यह कह दिया है कि अभी बसिज का किराया कम करने का सरकार को कोई विचार नहीं है और आज यह हालत है कि सरकार की तरफ से टूटी फुटी बसिज चलाई जा रही है और उन्ही बसिज से सराकर को काफी आमदनी हो रही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जब सरकार को बसों से काफी आमदनी हो रही है तो फिर किराया बढाने का सरकार का क्या ओचित्य है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजला: अध्यक्ष महोदय, मैं स्वामी जी को यह बता देना चाहता हूं कि हमारा खर्चा पहले से काफी बढ़ा है। यह 1973–74 में एक किलोमीटर पर 127.7 पैसे था, 1975–76 में यह खर्चा बढ़कर 164.6 पैसे हो गया और आजकल 184 पैसे एक किलोमीटर के हिसाब से हमारा खर्चा हो रहा है। अतः इस वक्त अगर इस फेयर को घटाया गया तो सरकार को काफी नुकसान होगा।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य संसदीय सचिव महोदय नरे जो उत्तर दिया है उस में उन्होने प्रति किलोमीटर के पीछे खर्चे का जिक किया है।। मै उन से यह जानना चाहात हूं कि क्या इसी कारण से दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हरियाणा स्टेट में बसिज का किराया जयादा लिया जा रहा है। इस वक्त हमारी स्टेट में छः या साढ़े छः पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज किया जाता है हमारी साथ की दिल्ली स्टेट में साढे तीन

पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किा जा रहा है, यह इतना अन्तर क्यों है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने जो छः या साढ़े छः पैसे किराया जिक किया है, वह गलत हैं। मैं उनकों यह बता देना चाहता हूं कि सारी स्टेट में जहां पर पक्की सड़कें है, उन पर आर्डीनरी बसों द्वारा सफर करने वालों से 4 पैसे प्रति किलोमीटर जार्च किया जाता है और अन–मैटल्ड रोडज पर आर्डीनरी बसों द्वारा सफर करने वालों से 5 पैसे प्रति किलोमीटर चार्ज किया जाता है। एक्सप्रैस बसिज द्वारा 5 पैसे प्रति किलोमीटर, लग्जरी सबिज द्वारा 8 पैसे प्रति किलोमीटर और एयर कंडी ंड बसिज द्वारा सफर करनें वालों से 12 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। यानि हरियाणा में जो आर्डीनरी बसजि से सफर करते है उन से 4 पैसे प्रति किलोमीटर, के हिसाब से चार्ज किया जाता है जोकि दूसरी स्टेटों से कम हैं अगर माननीय सदस्य दूसरी स्टेंटों की फिगर्ज भी चाहते हों तो मैं वह भी बता देता हूं।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महादेय, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहता हूं....(ाोर)

श्री अध्यचक्षः स्वामी जी, पहले आप मुख्य संसदीय सचिव महोदय का जवाब तो सुन लीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी की जानकारी के लिये मैं दूसरी स्टेटों का प्रति किलोमीटर केक हिसाब से फेयर बता देता हूं– गजरात के अन्दर 5पैसे, महाराश्ट्र के अन्दर 6 पैसे, कर्नाटक में 5.38 पैसे, मध्यप्रदे ा में 4.30 पैसे, आन्ध्र प्रदे ा में 5 पैसे, केरल में 5 पैसे, यू0पी0 जो कि हमारी साथ लगने वाली स्टेट है वहां 6.19 पैसे है, बिहार में 5.50 पैसे, हिसमाचल प्रदे ा में 3.50 पैसे, उड़ीसा में 4.40 पैसे और नागालैण्ड में 10.6 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जब कि हरियाणा में 4 पैसे है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारी सरकार यह कहती है कि हम गरीबों का भला करना चाहते है और दूसरी और बसजि का किराया बढाया जा रहा है। क्या सरकार उन गरीब मजदूरों और किसानों के लिये इस बस किराये में किसी प्राकर का कोई सं ोधन/छूट देने का चिार रखती है?

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, यह कोई सवाल नहीं बनता। मेरे विचार में मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने जो दूसरी स्टेटों की किराये की स्टेटमेंट पढी है, उससे जाहिर है कि हमारे हरियाणा में दूसरी स्टेटों की निस्बत किराया तकरीबन कम है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा स्टेट का बसों का किराया तकरीबन

दूसरी स्टेटों से कम है। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यह किराया टैक्स लगने के बाद भी दूसरी स्टेटों से कम रहेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि अभी सैन्ट्रल बजट आया है। उसके पास होने के बाद यह पता चलेगा कि और स्टैटों में किराया बढा है कि नहीं, तभी इस बारे में बातया जा सकेगा और मार्च के बाद ही सही पोजी ान का पता चल सकेगां

स्वामी आदित्यवे ाः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि जो विमुक्त जातियों के लोग या दूसरे साधन हीन लोग है, उनको इस बढते हुये किराये से छूट देने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः जी नही।

मुख्य मंत्रत्री (चौधरी देवी लाल): स्वामी जी, बस में आपकी टिकट ज्यादा लगेगी और वजन के हिसाब से लगेगी। (हंसी)

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने बताया है कि हरियाणा में 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता हैं मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर से अम्बाला छावनी 8 किलोमीटर है और इसका किराया 80 पैसे चार्ज किया जाता है,

क्या यहां पर भी 4 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया चार्ज किया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर इस बारे में मुझे लिखकर दे, मैं इसी सै ान में इसका जवाब दे दूंगा।

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, अभी स्वामी जी ने पूछा कि जो विमुक्त जाति या गरीब मजदूर लोग है क्या उनके लिये सरकार किराया में कुछ रियायत करने का विचार रखती है। मैं अपनी सरकार से यह जानना चाहात हूं कि इस दे ा के अन्दर ये मोटे बाबा जी साधू और सनयासी लोग है क्या उनको ीी इस तरह की रियायत देने का सरकार का विचार है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला किया है कि जो अपंग, लंगडे–लूले लोग है, उनको हरियाणा रोडवेज में फ्री आने जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह ओजलाः जी हां, अभी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का फैसला लिया है कि उनको फ्री करने की इजाजत है।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मैं क्लायर कर देना चाहता हूं। अभी कहा गया है कि मुख्य मंत्री ने यह फैसला ले लिया है कि लंगडे औ।र लूले मुफ्त ट्रेवल करेगें। यह गलत बात है। फैसला यह लिया गया है कि अगर किसी का ऐक्सीडेंट की वजह से हाथ या पैर कट जाए और उसे इलाज के लिये चण्डीगढ़ आना हो तो उसके लिये और उसके साथ एक आदमी के लिये आने जाने का फ्री ट्रेवल होगा। यह फैसला लिया गया है । वरना तो सारे ही फ्री चलते रहेगें।

Persons Killed and injured in Police Custody

***1029. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of persons who were injured, killed or died separately in Police custody during the period from Ist January to 31st December, 1978;

(b) the number of persons who were injured in Police lathi charge and killed in police firing during the afore-said period.

(c) the number of cases of atrocities on Harijans, and Backward Classes which were reported during the above period; and

(d) the total number in which the Police resorted to lathi charge on students, factory workers in the State during the months of January to December, 1978?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जख्मी भून्य

मारे गये भून्य

मरे भून्य

(ख) पुलिस लाठी चार्ज से 4 जख्मी

पुलिस गोली से 7 मरे।

(ग) हरिजनों पर अत्याचार के कोई केस नहीं हुये। फिर भी कुछ ऐसे केस थे जिन में हरिजन पीड़ित थे और दोशी गैर रहिजन। परन्तु यह केस वास्तव में व्यक्तिगत थे और इनका जाति, समुदाय आदि के प्र न से कोई सम्बन्ध नहीं था। उपरोक्त समय में ऐसे 68 केस (हत्या 3, बलात्कार 10, उत्पात 4, गम्भीर चोट1, आकमण 18, अपहरण 9, छेडछाड़ 19 और छुआछात 4)दर्ज हुये।

(घ) विद्यार्थियों पर एक बार।

कारखाना कर्मचारियों पर —कभी नहीं।

राव दलीप सिंहः मंत्री जी ने बताया है कि 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1978 तक चार आदमी जख्मी हुये और सात आदमी पुलिस फायरिंगकी वजह से मारे गये। मैं जानना चाहता हूं कि यह सात आदमी कहां— कहां पर मारे गये?

श्री वीरेन्द्र सिंहः पुलिस फायरिगं में चार आदमी तो पंडरी में मारे गये जब निहगों की फायरिंग हुई थी। इसकी मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी भी हो चुकी है और अन्क्वायरी अफसर ने होल्ड किया है कि इसमें पुलिस की ज्यादती नही थी। एक आदमी पानीपत में मारा गया और एक आदमी इन्दाना में मारा गया और एक गारावाली में मारा गया।

राव दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जो आदमी पानीपत में मारा गया क्या वहं इंडस्ट्रियल झगडे की वजह से मारा गया या और कारण से ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इंडस्ट्रियल झगड़े की वजह से नहीं मारा गया बल्कि उसने रात को पूलिस अफसर को थ्रैट किया था और पुलिस मुकाबले में वह मारा गया।

राव दलीप सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि हरिजन औरतों के नै किडनैपिंग के केस हुये। क्या इन केसलि में किसी को सजा हुई है या नहीं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये।

Consumers Cooperative Store at Nathusri

***888. Shri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the Consumers Cooperative, Store at

Nathrusri Chopta in Darbha Kalan constituency of District Sirsa, if so, the time by which it is likely to be opened?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

श्री अध्यक्षः मैं यह इमैजन नहीं कर सकता कि कोई मैंबर बेंचिराग गांव में भी कंज्युमर स्टोर खोलने की बात पूछ सकता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, नथूसरी के पास एक गांव है वहां हमने एक स्टोर खोल रखा है।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कंज्यूमर स्टोर किस साल से खुले हुये है और ये क्या काम कर रहे हे और इन स्टोरों की देहाती लोगों से नजर केसे मिल रही है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, स्परी स्टेट मे 17 कंज्यूमर स्टोर्ज है और 170 उनकी भाखाएं है ं। इसके अलावा नीचे लैवल पर सारी स्टेट में 1866 उपभोक्ता भंडार है जिनके द्वारा सस्ता कपड़ा, चाय , साबुन और मिट्टी का तेल सप्लाई किया जाता ह। इसके अलाव मै ंयह भी बताना चाहता हूं कि हमने यह भी फैसला लिया है कि 5 हजार की आबादी के उपर के जितने भी गांव होंगें उन सभी गांवों में 30 अप्रैल तक उपभोक्ता भण्डार खोल दिये जायेगें।

श्री मूलचन्द मंगलाः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सारे हरियाणा में लगभग दो हजार कंज्यूमर स्टोर है ंमैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने लाभ मे ंचल रहे है और कितने हानि में चल रहे है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन उपभोक्ता भंडारों का मं ाा प्रोफिट कमाने से नहीं है। यह तो इसलिये खोले गये है ताकि गरीब आदमियों को चीजें ठीक भाव पर मिलें और जिस इलाके में जिस चीज की कमी है वह चीज वहां पर इनके द्वारा मुहैया की जा सकें इनका मतलब सेवा भाव से है न कि प्रोफिट से।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि कंज्यूमर स्टोर कितने देहात मे ंहै और कितने भाहरों मैं है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 170 मे से 20 देहात में है।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, जो कंज्यूमर स्टोर इस वक्त हरियाणा में चल रहे है, उनके बारे में आम लोगों में ऐसा विचार सा बन गया हे कि उनका काम ठीक नही है। और उनमें कप ान ज्यादा चल रहा हैं कया मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि सरकार के पास करप ान रोकने के लिये जो एजेंसी है उसी को तेज किया जाएगा या स्टोरों के लिये अलग से कोई और

एजेंसी बनाई जाएगी जिससे कि इन स्टोर्ज से करप ान दूर हो सके?

चौधरी भजन लालः हम कोआप्रेटिव अदायरे में एक फलांइग स्कवायड बनाने जा रहे है उसमें एक सीनियर अफसर होगा जैसे ज्वायंट रजिस्ट्रार है, चार इंस्पैक्टर्ज होगें, एक ए0आर0 और एक डी0एस0पी0होगा। ये पूरी चैकिंग करेगें। जहां पर करप ान का केस मिलेगा उसके साथ पूरी सख्ती से निपटा जाएगा।

कंवर रामपाल सिंहः मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कंज्यूर स्टोर प्रोफिट के लिये नहीं खोले गये लेकिन मेंबर साहब ने सवाल यह पूछा था कि इनमें से कितने स्टोर घाटे में चल रहे है और कितने मुनाफें म`चल रहे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्टोर लौस में चल रहे हे उनके लौस में चलने के क्या कारण है?

श्री अध्यक्षः वैसे तो इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये लेकिन अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो दे सकते है।

चौधरी भजन लालः जैसे मैंन अभी कहा कि इन स्टोरों का मं ाा प्रोफिट कमाने का नहीं है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कंज्यूमर स्टोर्ज में कोई खास घाटा नहीं है।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 170 स्टोरों में से केवल 20 स्टोर देहातो ंमें है। भाहर वालों को तो पहले से ही सारी सुविधा उपलब्ध होती है और गांव वाले बेचारे दुखी है। क्या गांवों में इनकी संख्या और बढाई जाएगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैनें अभी कहा कि स्टेट में टोटल 1866 उपभोक्ता भंडार है जिनमें से 716 भंडार मिनी बैंक्स के द्वारा देहात में माल सप्लाई करते है ओर कुछ दूसरे भी है। जहां कहीं भी कमी महसूस की जाएगी तो अव य ही देहात में कंज्यूमर स्टोर खोल दिये जायेगें।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि 30 अप्रैल तक सभी 5 हजार की पापूले ान से जयाद के कस्बों, गांवों में कन्ज्यूमर स्टोर खोल दिये जायेगें। क्या मंत्री महोदय का यह भी विचार है कि कम पापूले ान वाले गांवों में भी ये कंज्यूमर स्टोर खोले जाये और वहां के लोगों को एम्पलायमेंट दी जाये?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 222 गांव है जिनमें से 104 में ये स्टोर खोल दिये गये है बाकी में 30 अप्रैल तक खोल दिये जायेगें। और उमें हमारी कोि ा ा होगी कि उनही क्षेत्रों के लड़के लगायें जायें और कम आबादी वाले गांवों में मिनी बैंक

द्वारा पहले ही खोले जा चुके है और जहां भी कमी होगी और खोल दिये जायेगें।

चौधरी हरिचन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, ये मिनी बैंक और कंज्यूमर स्टोर का क्न्फयूजन क्यों पैदा कर रहे है?

लाला बलवन्त राय तायलः क्यामंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जो कंज्यूमर स्टोर लौस में या प्रोफिट में चल रहे है इनमें से आप किनको सबसिडाईज कर रहे है?

चौधरी भजन लालः हमारी कोि ा ा यह होती है कि सब को सबसिडाईज करें और जो लौस में चल रहे है उन कंज्यूमर स्टोर्ज का हम सबसिडाईज करते है।

श्री भले रामः जो घाटा हो रहा है उसका उपबन्ध करने की क्यों नही कोि ा ा की जाती?

चौधरी भजन लालः हमारा उद्दे य स्टोर्ज खोलने का यह नीं है कि फायदा उठाया जाये बल्कि हम कम दाम पर गरीब लोगों को चीजें उपलब्ध करवाते है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में ग्रामीण उद्योगीकरण का अभियान बडी तेजी से चलाया जा रहा हैं इन उपभोक्ता भण्डारों में मिलों, फैक्टरियों का बना हुआ माल बेचा जाता हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या इन उपभोक्ता भण्डारों में

ग्रामीण उद्योगें से तैयार सामान बेचने का प्रबन्ध किया जायेगा जिससे गांव में बना हुआ माल ही गांव में लग सकें?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पहले ही फैसला किया हुआ है कि जो भी कोआप्रेटिव सोसायटियां माल बनायेगी उसको परचेज करके गांव में इन स्टोर्ज के माध्यम से बेंचेगें। हम इन सोसायटियों द्वारातैयार माल भी परचेज करेगें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि 5 हजार की जनसंख्या वाले गांव में कंज्यूमर स्टोर खोले जायेगें। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस गांव की जनसंख्या थोडी है वहां के लोगों को जयादा सुविधायं दी जायें ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढावा भी मिल सके?

चौधरी भजन लालः 5 हजार से कम वाले गांवो में मिनी बैंक खोले गये है इस तरह हर पटवार सर्कल में मिनी बैंक खोले गये है जिनके माध्यम से पूरी–पूरी सुविधा सब को दी जाती है।

Brideg on Yamuna Canal

***1149. Chaudhri Bhagmal:** Will the Minister for Public works be pleased to state-

(a) the date on which the bridge on Yamuna Canal, at Yamuna Nagar was built;

(b) whether it is a fact that it is so narrow that it is uite unfit for traffic ; and

(c) whether there is also any proposal under consideration of the Government to reconstruct the aforesaid bridge; if so, the time by which it is likely to be reconstruct?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह): मैं मोहतरमा सुशमा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाबी में सवाल का जवाब दे सकता हूं?

श्रीमती सुशमा स्वराजः तुसी सरदार साहब किसे बी भाशा विच जवाब दे सकदे हो, असीं वी पंजाबी विच सवाल पुछ लवांगे। (हंसी)

श्री लछमन सिंहः इह जो पूल दे बनण दी तारीख पूछी गई है दसी नहीं जा सकदी। इह 19वी सदी विच बणिया सी, बहुत पुराणा पुल है हुण, इस नूं दोबारा बणान लई 6–3–1979 नूं सरकार तो सैक ान मिल गई है, इस दी कौस्ट 34 लक्ख 95 हजार रूपये मंजूद कर दित्ती गई है। अच्छी तरां ते नहीं किहा जा सकदा पर 1979 विच इसदा कम्म भ्ारू हो जायेगा।

चौधरी ई वर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यमुना नगर में नया पुल बनाने की क्या स्कीम है?

श्री लछमन सिंहः इह किसे स्कीम दे अधीन नही है इस तरां दे सारी स्टेट विच पुल बण रहे ने। इह जनरल कवै चन है किसी खास जगह दे बारे नहीं है।

श्री दीपचन्द भाटियाः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि पलवल के पा जो हरियाणा और यू0पी0 के वीच पू बनना था जिसका फाउंडे ान स्टोन भी रखा गया था वह कब तक बनना भ्ारू होगा?

श्री लछमन सिंहः उसदे लई टेंडर काल कर लये हन, पुल ते बणने ही ने।

श्री फतेहचन्द विजः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने फरमाया है कि पुल 19वीं सदी में तेयार हूआ था। क्या आप कागजात देखकर बतायेगें कि इस पुल की मियाद कितनी मुकर्रर की गई थी और यह कब तक की है?

श्री लछमन सिंहः इह इस वक्त मैं दस नहीं सकदा क्योंकि मेरे कोल रिकार्ड नहीं है। मेरे कमरे ते आके मिल लवों तों असी इन्कवायर कर के दस दवांगें।

श्री जय नारायण वर्माः क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यह जो पुल 19वीं सदी में बना था क्या इसकों दोबारा बनाने की सोच रहे है?

श्री लछमन सिंहः इह तुसीं लिख के दे दिओ ते फिर इन्क्वायरी करके दस दिओगे।

चौधरी गंगा रामः मेरे इलाके में जो एक पूल टूटा हुआ है वह कब तक बन जायेगा?

श्री लछमन सिंहः इह गंगा राम दे विआ तक बण जायेगां (हंसी)

चौधरी देस राजः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि यमुना रिवर पर करनाल जिले में पुल बनाने की कोई स्कीम है?

री लछमन सिंहः तुाडा किस पुल नाल मतलब है उत्थे ते दो पुल ने। भारत सरकार नाल इस बारे गल बात चल रही है फैसला होण वालाहै।

डा0 बृज मोहन गुप्ता': स्पीकर साहब अगर बात करनी हो तो मंत्री जी कहते है कि कमरे में बात करेगें उनको कमरे की बजाये कार्यालय कहना चाहिये।

श्री अध्यक्षः पंजाबी में कार्यालय को कमरा कहते होगें।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, देखों पंजाबी विच गल करण दी किन्नी दिलचस्पी पैदा हो गई है। सुशमा जी, अग्निवे ा जी भी किन्ने खु ा हन।

श्री अध्यक्षः मैं हाउस के सभी सदस्यों को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि सभी मेंबर पंजाबी को इतना प्रोत्साहन दे रहे है।

Partity amonst H.C.S. (Judical) with H.C.S. (Executive)

***1153. Shrimati Sushma Swaraj:** Will the minister for Finance be pleased to state:

(a) whether the Government has taken any decision for bringing at par the pay scales other facilities of the H.C.S. (Judicial with those of H.C.S. (Executive Branch); and

(b) if so, the details thereof together with the time by which the said decision is likely to be implemented?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) तथा (बी) एच0सी0एस0 (न्यायिक भाखा) के वेतनमानों को एच.सी.एस. (कार्यकारी भाखा) के बराबर दिनाकं 1—1—1977 से कर दिया गयाहै। उनके सिलेक ान ग्रेड पदों को भी बढ़ा कर एच0सी0एस0 (कार्यकारी भाखा) की भांति 20 प्रति ात कर दिया गया है ।

(10.00 बजे):—

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या इन नये वेतनमानों के मुताबिक जूडि ायल अफसरों को वेतन मिलना भुरू हो गया है?

चौधरी देवी लालः जब उसका फैसला हो गया हे तो उस पर अमल भी होना जरूरी होता है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि उनको वेतन मिलना भुरू हो गया है या नहीं?

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री महोदय ने तारीख दे रखी है जिससे the pay scales have been brought at par.

चौधरी हरस्वरूप बुराः अध्यक्ष महोदय, पे तो बराबर हो गई लेकिन मै मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कछ जजिज साहिबान जिन के पास टेलीफोन नहीं है क्या उनको टेलीफोन की सुविधायें प्रोवाइड की जाएंगी?

चौधरी देवी लालः जूडि ायरी के अफसरों को भी जो सहूलियतें एग्जैक्टिव ब्रांच में दी जाती है, वही सहूलियतें दी जाएगी।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि हमारी जानकारी के मुतपगि उन्हे वेतन मिलना भुरू नहीं हुआ है। क्या मुख्य मंत्री महोदय

सपश्ट करेगें कि क्या वेतन मिलना भ्रुरू हो गया है और अगर हां तो कब से मिलना भ्रुरू हो गया हैं?

Mr. Speaker: Once the Government has taken a decision, I am sure it will be implemented. There should be no doubt about it.

तारांकित प्र न संख्या 984

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी संत कंवर, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Embezzlement in the Cooperative Societies

***909. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether any embezzlement has been detected in the Cooperative Societies during the period from 4th July, 1977 to 4th July, 1978 in the State;

(b) if so, the total amount involved and details thereof; and

(c) the amount, if any , recovered so far together with the number of officials category-wise found guilty and action taken against them?

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां जी।

(बी) उपरोक्त अवधि में गबन के 250 मामले पकड़े गये । उनमें कुल रा ि ा 26.77 लाख सम्मिलित है। जिलेवार विवरण सदन क पटल पर रखा जाता है।

(ग) अब तक 54 मामलों मे मुबलिग 2.56 लाख रूपये की रा ि ा वसूल की जा चुकी है। इन 250 मामलों में 289 व्यक्ति ग्रस्त हैं इनमें से 184 मिनी बैंक मैनेजर तथा सचिव, 12 विक्रेता तथा स्टोर कीपर 6 क्लर्क/कार्यकारी अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी और 86 समितियों के प्रबन्धक कमेटी के सदस्य है। 16 व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में केस दिये गये है और 73 के विरूद्ध पुलिस में तफती ा अधीन है। विभाग की ओर से 200 व्यक्तियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही चालू कर दी गई है।

क्रम संख्या	**जिले का नाम**	**गबन जो 4–7–77 से 4–7–78 तक की अवधि में पकडे गये (रा ि ा लाखों म)**	
		संख्या	**रा ि ा**
1	अम्बाला	12	2.34
2	भिवानी	6	1.00
3	गुड़गांव	50	3.60

4	हिसार	15	2.54
5	जीन्द	13	1.01
6	करनाल	18	5.57
7	कुरूक्षेत्र	11	0.59
8	महेन्द्रगढ़	7	1.65
9	रोहतक	33	4.18
10	सिरसा	21	1.73
11	सोनीपत	64	2.56
कुल		**250**	**26.77**

स्वामी आदित्यवे ा: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 250 में से कुल 54 मामलों में 2 लाख 56 हजार रूपये वसूल किये गये तो बाकी रूपये को कब तक वसूल किया जायेगा और बाकी व्यक्तियों को कब तक दण्डित करवाया जायेगा?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मैने सवाल से जवाब में बताया है कि कुछ केसिज की पुलिस में तफती ा चल रही है और कुछ केसिज में महकमा वसूली की कार्यवाही कर रहा है तथा कुछ केसिज अदालत में है। जो केस

अदालत में है उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक फैसला होगा लेकिन जो केसिज पुलिस के पास है उनकी हम कोि ा ा करेगें कि वह जल्दी से जलदी उन केसिज की जाचं करके कोर्ट में भेज दे ं ताकि निपटान भीघ्र हो सके।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट में हमारे मंत्री जी के साथ हिसार के बाबू गुलाब सिंह जैन हुआ करते थे। उन साहब ने इन सोसाइटियों के अन्दर बडा भारी गबन किया था और यह बस के नोटिस में हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होने यह जो सूची दी है उस सूची में उनका नाम है या नहीं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जुलाई टू जुलाई इसी साल का पूछा है पीछे का नही पूछा। वैसे मैं अगर टोटल बतांउ तो 979 व्यक्तियों के खिलाफ गबन के केसिज चल रहे है। इनमें अमांउट भी करीब 1.90 करोड़ रूपये इनवालब्ड है। कुछ साल पहले सयो ाल वैलफेयर का महकमा मेरेंपास हुआ करता था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा, चाहे मख्य मंत्री जी फाईल मंगवा करके देख लें कि जिस भद्र पुरूश का नाम इन्होने लिया है उसके बारे में मैनें उस समय भी फाईल पर लिखा था कि इस आदमी ने गलत ढंग से पैसा लिया है इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए उसके बाद भायद चौधरी बंसी लाल जी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौधरी बंसल लाल जी ने तो कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन क्या अब यह सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार है या नहीं?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): मेरे साथी श्री जगननाथ जी की याददहानी के लिये भाुकिया । इस पर अमल जरूर होगा।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदयख, जब यह सोसाइटीज बनाई गई थी और जो आदमी सोसाइटी बनाने वाले थे उन्होने हस्ताक्षर और किसी के करवा दिये और जो पैसा दिया गया वह पैसा खुद ले करके इम्बैजलमैन्ट कर दी। कुछ केसिज तो उन लोगों पर चल रहे है और जिनके झूठे नाम लिखे गये वह हम सरकार के नोटिस में लाये है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि जिन्होने झूठे नाम लिखे है उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, बूरा साहब ने ठीक कहा है। इस किस्म के केसिज बहुत हैं अब उसमें दिक्कत यह है कि कुछ दिन पहले तक सोसाइटीज में ऐसी प्रथा रही है कि सोसाइटीज के प्रैजीडेंट या सैकेटरीज जो होते थे वही उसके सदस्य होते थे। वह जो रूपया बैंक से लेते थे वह किसी भोले आदमी को 100 रूपये दे करके 1000 पर अगुंठा लगवा दिया करते थे। इस किस्म के केसिज बहुत है इसकी इंकवायरी चल रही है

लेकिन इस सारे ढांच को हमने बदला है ताकि कोई गड़बड़ न हो और कोई हेराफेरी न हो। इसके लिये हमने पास बुक जारी की है और पास बुक के साथ–2 फोटो की प्रथा भी जारी की है ताकि कोई गलत आदमी गलत ढंग से पैसा न ले सके।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः मैं मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि क्या इन केसिज में यमुना भूगर केन डिवैल्पमेंअ सोसाइटी के मैंबर वाला केस भी है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोद, भूगर केन वाला केस इसमें नही हैं ।

सरदार सुखदेव सिंहः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हामरे एक श्री विराज सिंह एम0एल0ए0 बनते बनते रह गये क्या उनका नाम भी इस लिस्ट में है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर एक माहनुभाव का नाम लिया तो उसके बारे में हम इंक्वायरी करवा लेगें अगर उन्होने कोई गड़बड़ की है तो उनको भी बख्भाा नहीं जायेगा।

श्री गुलजार सिंहः अध्यक्ष महोदय, गबन के केसिज जो है इनमें वसूली का जो तरीका है वह बहुत ही लम्बा, टेढ़ा है और काफी साल तक आदमी काबू नहीं आते। क्या मंत्री जी ऐसा कोई ढंग सोचेगें कि जो बड़े बड़े आदमी कई लाख का धन दबाये बैठे है उनसे किसी सरल तरीके से वसूली की जायें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में 9858 सोसाइटीज है और हमने गबन को रोकने के लिये फैसला किया है कि हर सोसाइटी का एक साल के अन्दर–अन्दर ओडिट हो जाए। हमने पिछले साल 9858 मे से 9405 सोसाइटीज का औडिट करवाया और जिस किसी के खिलाफ कोई गबन की बात मिलजी उसके खिलाफ हमने फौरान कार्यवाही भ्ारू की है ताकि जल्दी ही केसिज के फेसले हो जाएं और गबन कम हों।

चौधरी पीर चन्दः मंत्री महोदय ने बताया है कि 100 रूपये की जगह 1000 रूपये किसी गरीब आदमी के नाम लिख दिया और अगुंठे लगाकर उनकों कर्जदार बनाया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या ऐसे केसिज की रिकवरी सरकार ने बन्द कर दी है ओर जिन से गलत रिकवरी होगई है, क्या उनको वह रूपया वापिस करने की बात सरकार के विचारधीन है?

चौधरी भजन लालः इस किस्म के केसिज कानून की जद में नहीं आ रहे है और वे लोग कानून की आड में फंसे हुये है। होि ायार लोगों ने झूठे अंगूठे और झूठे दस्तखत करवा लिये है और हमारे सामने यह बहुत बड़ी समसया हैं हम पूरी कोि ा ा करेगें कि जिन्होने वास्तव में पैसा लिया ही नहीं, वैसे ही गरीब आदमियों के नाम लिख दिया है, उन्हे इन्साफ मिले लेकिन कानूनी तौर पर हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ रही है क्योकि अगूंठा या

दसतखत उसी आदमी के है जिसके नाम उन्होने ज्यादा रकम लिख रखी है।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, जिला जींद में डिस्ट्रिक्ट स्टोरों में लाखों रूपये की ऐम्बैजलमेंट हुई है। क्या मंत्री महोदय इसकी इन्कवायरी करके दोशियों को दण्ड देने की कोि ा ा करेगें?

चौधरी भजन लालः इनके खिलाफ बहुत जल्दी सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कोि ा ा करेगें। जिन लोगों ने गड़बड़ और हेराफेरी की है, उनको बख्भाा नहीं जायेगा।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय बाद में आये है, इनका कसूर नहीं है, लेकिन अब चूंकि मंत्री है ,इसलिये इनको जवाब तो दना ही पड़ता है। क्या मेरे पापूलर मंत्री महोदय बतायेगें कि जिन लोगों से अगूंठे टिकटा लिये, पैसे दिये ही नहीं, जैसे थाना थपरा में इस किस्म के बहीुत से केसिज दर्ज है और वहां पर लाखों रूपये की गड़बड़ कर रखी है और जिन लोगों ने गड़बड़ की है वे उसी तरह मौज कर रहे है। क्या मंत्री महोदय इनके खिलाफ कार्यवाही करने का अ योंरेस देगें?

चौधरी भजन लालः इस बात का पहले भी कई दफा जिक आया है। इस के लिये हमने बहुत सी जगह पर सालस मुर्कररर किये हुये है और इससे पहले महकमे ने पूरी कोि ा ा की थी कि ये केसिज अदालतों में भेज दियें जांये लेकिन अदालतों मे

कामयाबी नहीं मिली। इसी लिये सालस मुकर्रर किये है। और ऐसे केसिज का निपटारा सालस मुकर्रर करने से ही हो सकता है ताकि यह पता लगे कि जिन्होने वास्तव में रूपया लिया है उन से वसूल किया जाये और जिन के झूठे अंगूठे लगे है वे परे ान न हों ओर उन्हें इन्साफ मिल सके।

श्री अध्यक्षः लास्ट सप्लीमेंटरी स्वमी आदित्यवे ा जी करेगें। वैसे यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस विशय पर पूरी तरह से सोच विचार करें। लोगों पर बड़ा सख्त जुल्म हुआ है, गरीब लोगों के दस्तखत गलत ढंग से करवाकर दूसरे लोग पेसा ले गये है। मैं भी मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस विशय पर पूरी तरह सोच विचार करके निर्णय लें।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, पहले जो प्रणाली थी वह ठीक नहीं थी। यह जो गड़बड़ है यह चार पाचं साल पहले की गड़बड़ है और इसको चैक करने के लिये हमने औडिल्ट पार्टी और फलाइंग स्क्वैड का इन्तजाम किया और हम एक–एक चीज की जांच करेंगें। जहां तक हमें कानन इजाजत देगा, हम उन लोगो की पूरी मदद करेगें और जिन लोगों ने झूठे अगूंठे लगवाकर कर्जा लिया है , उसकी वसूली उन्ही लोगौं से करने की कोि ा ा करेगें जिन लोगों ने सही मायनों मे पैसा ले रखा है।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, करनौल जिले में 18 आदमियों ने 5 लाख 57 हजार रूपये का गबन किया है और यह गबन सब जिलों से ज्यादा है। क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि यहां सब से ज्यादा गबन होने के क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं बनता। उन्होनें गबन किया है, कारण कोई भी हो सकता और मंत्री महोदय ने आ वासन दिया है कि इसके बारे मे पूरी कार्यवाही करेगें।

Vacancies of B.A., B.Ed. Teachers

***1084. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a large number of posts of B.A., B.Ed. teachers are lying vacant at present in the Government Middle and High Schools in the State;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the proposal if any under consideration of the Government to recruit the B.A., B.Ed. teachers for fillng up the vacant posts; and

(c) the mode of recruitment?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) जी नहीं।

(बी) तथा (सी) 'ए' को ध्यान में रखते हूये प्र न पैदा नहीं होता।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदय बतायेगें कि स्कूलों मे ंसरकार मैथेमैटिक्स टीचर्ज तथा साईस मास्टर्स की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है, उन पर बैन क्यों लगा रखा है और क्या सरकार इस बैन को हटाने की कृपा करेगी?

श्री हीरानन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के भाासनकाल में लगभग 1600 के करीब सो ाल स्टडी मास्टर्ज की नियुक्ति , साईस तथा मैथेमैटिक्स टीचर्ज की पोस्टों के अगेनस्ट की थी और ये 8–10 साल पुराने हो चुके है। इनको ऐबजोर्ब करना है। बहुत सारे तो ऐबजार्ब हो चुके है लेकिन तकरीबन एक हजार के करीब ऐबजार्ब हजोना बाकी रहेते है। पहले इनको ऐबजार्ब करना है, इसलिये नये टीचर लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री जय नारायण: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि पहली सरकार ने बहुत ज्यादा अध्यापको को लगा दिया था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन को कम करने का विचार रखती है, यानि क्या इनकों हटा रही है?

श्री हीरानन्द आर्य: हटाने का तो प्र न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने कहा है कि ऐबजार्ब करने की पूरी कोि ा ा कर रहे है।

श्री मांगे राम गुप्ताः जो ओ0टी0 टीचर्ज स्कूलों में लगे हुये थे उनके बारे में डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर वे बी0एड0 कर लेगें तो उन के लिये 25 परसैंट कोटा रिजर्व कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बतायेगेक कि जिन ओ.टी. टीचर्ज ने बी0एड0 कर ली है क्या उनको 25 परसैंट की रिजर्वे ान के अन्तर्गत लिया गया है?

श्री हीरानन्द आर्यः माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है, 25 परसैंट की रिजर्वे न है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि एस.एस0मास्टर्स स्कूलों मे लगे हुये है, कोई जगह खाली नहीं है। हम कोि ा ा कर रहे है और यह मामला विचाराधीन है और जल्दी से जल्दी फैसला कर रहे है ताकि जिन लोगों ने बी0एड0 कर ली है, उनको रिजर्वे ान के तहत लगाया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराजः ि ाक्षा मंत्री जी ने सदन को यह जानकारी दी है कि हिन्दी और संस्कृत की पोस्टों पर एस.एस. मास्टर लगे हूये है ओर इसके साथ ही उनको ऐबजोर्ब करने की बात कर रहे है। मैं मंत्री से जानना चाहती हूं कि जो हिन्दी और संस्कृत के ट्रेंड टीचर बेकार बैठे है, उनको ऐबजोर्ब करवाने के लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे है?

श्री हीरानन्द आर्यः जो एस.एस. अध्यापक लगे हुय है वे चार पाचं साल के नहीं, बल्कि 10–10 साल के लगे हुये है।

वास्तव में एजुके ान के साथ, विद्यार्थियों के साथ बड़ा अत्याचार किया जाता रहा है। हम कोि ा ा कर रहे है कि इसका कोई न कोई रास्ता निकले। पहले एस0एस0 टीचर्ज ऐबजार्ब हो जायेगें, इसके बाद संस्कृत–हिन्दी मास्टर ऐबजार्ब किये जायेगें। हम एजुके ान के ढांचे को नये सिरे से तैयार कर रहे है।

श्री अध्यक्षः जो पुराने भाासनकाल के बारह तेरह सौ मास्टर लगे हुये है उनको इस वक्त मंत्री महोदय टर्मिनेट करना ठीक नहीं समझते ं

चौधरी ई वर सिहंः स्पीकर साहब, 1600 मास्टर तो पहले ही सरप्लस है इनको ऐबजार्ब करना है, जब तक ये ऐबजार्ब होंगें तब तक ट्रेंड टीचर्ज ओवर–एज हो जाएंगे। क्या मंत्री महोदय इन को नौकरयां दिलवाने के प्र न पर विचार करेगें ताकि ये ओवर–एज न हो जायें?

श्री हीरानन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुये ही हमने बी0एड0 की क्लासों को बन्द करने का फैसला किया है क्योकि 14–15 हजार बी0एड0 टीचर्ज आलरैडी एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज में दर्ज है इसलिये यह फैसला किया है।

श्री अध्यक्षः जो स्कूल अप्रेगड हो रहे है उनमें भी तो काफी ऐबजोर्ब हो जायेगें।

श्री हीरानन्द आर्यः 180 स्कूल अपग्रेड होगें, उनके मुताबिक ही ऐबजोर्ब होगे।

श्री जगननाथः अभी मिनिस्टर महोदय ने बहन सुशमा जी के सवाल के जवाब में उत्तर दिया है कि हम ि ाक्षा के सारे सिस्टम को बदलने जा रहे है। पिछले साल जो स्कूल अपग्रेड हुये यानि मिडल से हाई हुये हां पर संस्कृत और हिन्दी टीचर्ज की जगह एस0एसव0 मास्टर्ज लगाये गये है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि उन की जगह संस्कृत और हिन्दी टीचर्ज भेजने का कश्ट करेगें?

श्री हीरानन्द आर्यः उनको घर बैठे हुये तन्खाह तो हम दे नही सकते। जिन अध्यापको के पास बी0ए0 में संस्कृत और हिन्दी थी उन्ही एस0एस0 मास्टर्ज को उन स्कूलों में लगाया गया है ताकि वह हिन्दी और संस्कृत पढा सकें। मैं यह भी समझाता हूं कि इसका समाधान आसान नहीं है।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं मंत्री महोदय ने जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से बच्चों की तालीम खराब हो गई और वे तालीम से महरूम भी रह गये, क्या अब वहां पर उसी सबजैक्ट के टीचर्ज भेजने का कश्ट करेगें?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का जवाब पहले ही आ चुका है।

श्रीमती भाान्ति देवीः अभी मिनिस्टर महोदय ने बताया है कि एस0एस0 मास्टर्ज ही हिन्दी ओर संस्कृत टीचर्ज की जगह सुचारू रूप से पढा रहे है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना कि वे इसलिये सुचारू रूप से पढा रहे है क्योकि उनके

पास बी0ए0 में संस्कृत और हिन्दी विशय था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। एस0एस0 मास्टर्ज हिन्दी और संस्कृत नहीं पढा सकते है। मै ि ाक्षा मंत्री महोदय से आ वासन चाहती हूं कि ि ाक्षा का ढांचा बदलने से पहले जो हिन्दी और संस्कृत सबजैक्ट के टीचर्ज है क्या उनको वहां पर लगाया जायेगा जहां पर सबजैक्ट टीचर्ज नहीं है?

श्री हीरानन्द आर्य: सरकार इस बात को समझती है कि ि ाक्षा सुचारू रूप से नहीं दी जा रही है और हरियाणा में ि ाक्षा में काफी तबाही हुई है, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता लेकिन कोई पूरानी बीमारी हो तो उसका इलाज करने में समय लगता है। मैने उस बीमारी का इलाज करने का जिक किया है। हम इस बात के लिये वचनबद्ध है।

Confidential Reports of the Employees

***981. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:**

Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the previous government had passed orders about the confidential reports of the employees that at the time of promotion average reports are not even conveyed to the concerned employees; and

(b) whether the Government intend to consider the average report at the time of promotion, if not, whether the

Government propose to convey the average report, which is considered as bad report to the concerned employees?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) वर्श 1972–73 मे राज्य सरकार ने यह हिदायतें जारी की थी कि केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये विचार में लाया जायेगा जिन्होने कम से कम 50 प्रति ात गोपनीय रिपोर्ट 'अच्छी' या 'औरस्त से बेहतर' प्राप्त की हों इस के लिये कर्मचारियों की कम से कम पिछले 10 वर्श की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार यिका जाना होता है। यह ठीक है कि औसत रिपोर्ट कर्मचारियों को व्यक्त नहीं की जाती है।

(ख) जी नहीं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब जो अच्छे मुलाजिम होते है और मेहनत से काम करते है, वे अफसरों की खु ाामद नहीं करते इसलिये उनी रिपोर्ट गलत लिख दी जाती है लेकिन जो मुलाजिम अच्छे नहीं होते है और केवल खु ाामद करते है उनकी रिपोर्ट अच्छी लिख दी जाती है। क्या मुख्य मंत्री महोदय, द्वारा इस बारे में रूल में तबदीली करने पर कोई विचार किया जायेगा?

चौधरी देवी लाल: यह ठीक ख्याल नहीं है। जो मौजूदा सिस्टम है उसे तबदील करने की जरूरत नहीं है क्योकि अगर हम इस ढंग से अपने अफसरों द्वारा दी गई रिपोर्ट की बाबत भाक

करना भुरू कर दे तो सीनियर अफसरों की राय लेने का मुद्दा खत्म हो जायेगा। इसलिये यह सिस्टम चेंज करना मुनासिब नहीं समझा जा सकता।

चौधरी भागमलः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐवरेज रिपोर्ट को बैड कनिसडर नहीं करते है तो उसको गुड मानना चाहिये।अगर वह बैड समझते है तो उसको कनवे होनी चाहिये ताकि ऐम्पलाई आदन्दा अपने कैरियर को ठीक कर सकें।

चौधरी देवी लालः यह जो रिपोर्ट दी जाती है वह उसके काम पर और बिहेवियर पर दी जाती है। खास अच्छी बुरी बातों के जिक्र के अलावा इस रिपोर्ट में अफसर की अपनी ओवरआल राय भी होती है। जिसको कनवे करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, सामान्य रिपोर्ट को केवल सामान्य ही रहने देना चाहिये। मुझे आ ा है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब उसको अच्छी मानने के लिये तैयार नहीं है तो उसको खराब भी न मानने के लिये तैयार होगें?

चौधरी देवी लालः सामान्य को सामान्य समझ कर ही चला जाता है। उसको अच्छा नहीं लिया जा सकता है। वह जनरल असैसमेंट तो अफसर के अपने तजुर्बे की रो ानी में फैसला करने पर है।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडियाः मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि अगर सामान्य रिपोर्ट को लिखने से अधिकारियों का समय बरबाद करने वाली ही बात मानी जाती है और कर्मचारी का कोई फायदा नहीं होता तो क्यों नही इस सामान्य भाब्द को खत्म ही कर दिया जाता?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं बनता है।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, यहां हाउस में एवरेज रिपोर्ट का सवाल चल रहा है। जब हरियाणा, हिमाचल और पंजाब बने तो उस समय कुछ कांसिड्रे ान इसके लिये रखी गई थी। एक स्टेट जो फैसेलिटी देगी वही दूसरी स्टेट भी देगी। इसलिये पंजाब में ऐवरेज रिपोर्ट को अच्छा गिना जाता है। इसी प्रकार से हिमाचल में भी अच्छा गि?ना जाता है परन्तु हरियाणा में अच्छा नहीं गिना जाता। पिदली सरकार जानबूझकर आर्डिनैंस लाई कि ऐसरेज रिपोर्ट कन्सर्न्ड अधिकारी को कनवे न की जाये। अफसरान का क्या कसूर है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि उसकी रिपोर्ट खरब हो चुकी है। मैं चीफ मिनिसटर साहब से जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब में यह बात लागू है या नहीं?

चौधरी देवी लालः जहां तमक पंजाब और हिमाचल का ताल्लुक है इसके बारे में पता लगाया जा सकता हैं इस वक्त मुझे पता नहीं है लेकिन अगर ओवरआल असैसमेंट करवे करना भाुरू कर दे ंतो इसका मतलब यह होगाकि हर अफसर अपने अनुभव को

स्पश्ट लिख देने में हिचकिचायेगा। इसलिये कुछ न कुछ कौन्फीडेन्ि यलिटी रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः अगला क्वै चन।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मुझे अभी–2 पता लगा है कि औस्त दर्जे की रिपोर्टों को व्यक्त न करने के बारे में पंजाब और हिमाचल में भी इसी किस्म का स्स्टिम है जैसा हरियाणा में है।

Sub-yard Centres

***1160. Sardar Tara Singh:** Will the Minsiter for Agriculture be pleased to state-

(a) the number of Sub-yard Centres recently sanctioned for the Kurukshetra district togetherwith the location and the time by which such cnetres are likely to be set-up ; and

(b) whether any Sub-yard Centres as referred to in part(a) above arelikely to be set-up in village Gum,thala etc. in Kurukshetra district?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह): स्पीकर साहब, चालू साल में कुरूक्षेत्र जिले में कोई सबयार्ड यानी छोटी मंडी मंजूर नहीं हुई हैं जहां तक गांव गुमथला का सवाल है, ऐसे दो गांव है। एक गुमथला गांव में मंडी है, सब–यार्ड है और दूसरी जो गढद्यी है, उसके अन्दर हम मंडी बनाने का विचार कर रहे है।

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तांराकि प्र नों के लिख्ति उत्तर

Bus stand at Uklana Mandi

***974. Shri Jai Narain Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand at Uklana Mandi?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): अभी नहीं।

Furniture in Government High Schools

***995 Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) wheter adequate quantity of articles of furniture have been provided for students of the 9th and 10th classes in the Government High Schools in the Haryana State; and

(b) whether the Government is aware of the fact that there are not even Tats (Mats) in the High Schools of Haryana for students; if so, the steps taken so far or proposed to be taken for providing thefurniture?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(ए) नहीं। जब कभी माध्यमिक विद्यालय का स्तर उच्च विद्यालय तक बढ़ाया जाता है तो फर्नीचर के लिये रा ि ा निर्धारित नार्म के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है, परन्तु तत्प चात टूट फूट के फलस्वरूप या छात्र संख्या बढने की वजह से जो प्रयोगात्मक फर्नीचर में कमी पडती है, उसे पूरा करने हेतू कोई वि ोश रा ि ा की व्यवस्था नहीं है।

(बी) हां, सरकार यह जानती है कि राज्य में राजकीय स्कूलों में फर्नीचर की कमी है अधीनसि कार्यालयों से ुर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिये सूचना मंगवाई जा रही है और रा ि ा की उपलब्धि की अवस्था में इस कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जायेगें।

Suspension of ofiicers in General Administration

***1131. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a number of class I and II officers are under suspension in the General Administration Department at present; if so, since when; and

(b) whether the charge-sheets have been served upon all of them if not, the number of officers out of thos referred to in part (a above to whom the charge-sheets have not been served togetherwith the reasons therefore?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) तथा (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

निलम्बिल अधिकारियों की संख्या	कब से निलम्बित है	क्या आरोप पत्र दिया गया है या नहीं	कारण जिनके आधार पर आरोप पत्र, नहीं दिया गया
श्रेणी I-6	दो अधिकारी जुलाई 1977 से तथा नवम्बर 1977 से एक अधिकारी, फरवरी 1978 से तीन अधिकारी, फरवरी/मार्च 1979 से	नहीं दिया गया	चार अधिकारियों के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें लम्बित है, इसलिये उन्हे आरोप–पत्र जारी नहीं किये जाने है। बाकी तीन अधिकारीयों को, जिनको हाल ही में
श्रेणी II-1	सितम्बर 1977 से	नहीं दिया गया	

			फरवरी / मार्च 1979 में निलम्बित किया गया था, आरोप–पत्र भीघ्र ही दिये जाने की संभावना है।

Regional Engineering College Kurukshetra

***1100. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of students admitted every year in Regional Engineering College, Kurukshetra;

(b) the number of students f Haryana domicile who can be admitted in the said College out of those mentioned in part (a) above;

(c) whether the students of Haryana domicile are getting their full share of admission every year in the said College.

(d) the total number of students in the said College at present togetherwith the number of students out of them of Haryana domicile; and

(e) the total number of lecturers and other employees in the said College togetherwith the number of Haryana domicile?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(क) 1– बी0एस0सी0 इंजीनियरिंग कोर्स के लिये 250.

2–एम0एस0सी0 इंजीनियरिंग कोर्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिये 45.

(ख) केवल बी0एस0सी0 इंजीनियरिंग कोर्स के लिये 125 है तथा एम0एस0सी0 और पोस्ट ग्रेजूएट डिप्लोमा की सभी सीटें मैरिट के आधार पर भरी जाती है।

(ग) कालेज में बी0एस0सी0 इंजीनियरिंग के छात्रों की कुल संख्या 1213 है और एम0एस0सी0 इंजीनियरिंग तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा छात्रों की संख्या 48 है। बी0एस0सी0 इंजीनियरिंग कोर्स में हरियाणा निवासियो के लिये निर्धारित सीटों के विरूद्ध 602 छात्र है।

एम0एस0सी0 इंजीनियरिंग तथा पोस्ट गेजुएट कोर्स की सभी सीटें मैरिट के आधार पर भरी जाती है, तथापि प्रवे ा के समय 15 छात्रों ने अपने हरियाणा के पते दिये।

(ड़) कुल 426, जिसमें से 214 का स्थाई पता हरियाणा का है।

Distribution of funds by Soldiers, Airemen's and Sailors' State Board

***1111. Rao Ram Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a sum of Rs. 30000/- was distributed to 54 persons of Beri constituency during the year 1978 by Soldiers', Airmen' and Sailors' State Board of Haryana;

(b) the criteria adopted for the selection of these persons;

(c) whether it is a fact that the sum of Rs. 30000/- was drawn by the State Secretary of the above said Board from Haryana Defence and Security Relief Fund; and

(d) whether any fund was likewise distributed by the said Board during the year 1978 amongst persons belonging to other district/constituencies of the State, if so, the amount thereof in each case?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) वर्श 1978 के दौरान हरियाणा रक्षा तथा सुरक्षा सहायता निधि में से 30000/–रूपये की रा ि ा जिला रोहतक के 54 व्यक्तियों (33 सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा 21 निर्धन भूतपूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों)में (न कि केवल बेरी निर्वाचन क्षेत्र में ही) उपायुक्त एवं सचिव, हरियाणा रक्षा तथा

सुरक्षा सहायता निधि समिति ने अपनी भाक्तियों का प्रयोग करते हुये बांटी थी।

(ख) आर्थिक सहायता उन जरूरतमन्द भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों, युद्ध विधवाओं/भूतपूर्व सैननिकों की विधवाओं को दी जाती है जिनके पास आमदनी के पर्यापत साधन नहीं होते।

(ग) हां, श्रीमान जी।

(घ) इसी प्रकार की आर्थिक सहायता अन्य जिलों को भी दी जाती है। वर्श 1978 के दौरान बांटी गई रा ि ा तथा 1–1–78 से 28–2–79 तक उपायुक्तों को वितरण के लिये दी गई रा ि ा की जिलावार तफसील अनुबन्ध में दी गई है जोकि हाउस के मेज पर रखी है।

अनुबन्ध

वर्श 1978 के दौरान दी गई जिलावार सहायता

कम संख्या	**जिले का नाम**	**रूपये**
1	अम्बाला	1500
2	भिवानी	5000

3	गुड़गावं	10800
4	जीन्द	3300
5	महेनद्रगढ़	3721
6	कुरूक्षेत्र	2000
7	सोनीपत	300
8	रोहतक	30000
1—1—78 से 28—2—1979 तक उपायुक्तों को वितरण के लिये दी गई रा ि ा		
1	गुड़गावं	11800
2	करनाल	10000
3	जीन्द	21300
4	नारनौल	15921
5	सोनीपत	23600
6	भिवानी	5000
7	कुरूक्षेत्र	6500

8	रोहतक	30000
9	अम्बाला	1500

Roaster for promotion of persons belonging to Scheduled Castes/Backward Classes in the Education Directrorate

***1133. Captain Mange Ram:** Will the Minister for Educaiton be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Roaster for promotionof persons belonging to the Scheduled Castes and Backward classes in the Education Department has not been prepared; and

(b) if reply to part(a) above be in the affirmative, the reasons therefore?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरानन्द आर्य):

(क) नहीं।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

ध्यानाकर्शण सूचना

बद ाहपुर और उमरी (कुरूक्षेत्र) में भाराब के ठेकों की नीलामी सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मुझे स्वामी आदित्यवे ा, एम0एल0ए0 से जिला गुडगांव में गांव बाद ाहपुर और जिला कुरूक्षेत्र में गावं उमरी में भाराब के ठेकों के बारे में एक ध्यान दिलाऊ प्रस्ताव का नोटिस मिला है। प्रस्ताव मंजूर किया जाता है। आनरेबल मेंबर अपना प्रस्ताव पढ दे। एक्साइज एडं टैक्से ान मिनिस्टर चाहें तो अपना ब्यान दे सकते है या फिर समय मांग सकते है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप हिन्दी में जो काम हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दे ंतो उस को पढने वगैरा में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्षः इसके लिये तो जो टाइप की म ीनें बनाते हैख उनका ध्यान दिलाना पडेगा(वयवधान)

स्वामी आदित्यवे ाः मैं सदन का ध्यान अत्याव यक लोक महत्व के इस वि ाय अर्थात ' ाराब बन्दी' की और दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों में ग्राम पंचायतों ने उनकी पंचायतों से भाराब के ठेके हटाने के लि संकल्प पास किये तथा वे संबंधित मंत्री के भेज दिये गये थे। उन ग्राम पंचायतों में से प्रमुख ग्राम पंचायतें जिला गुडगांव की ग्राम पंचायत बाद ाहपुर तथा जिला कुरूक्षेत्र की ग्राम पंचायत उमरी है। इसके अतिरिक्त आबकारी मंत्री ने ग्राम पंचायत बाद ाहपुर के बारे मे ंसदन में यह स्वीकार किया

था कि ग्राम पंचायत बाद ापुर से संकल्प प्राप्त हो गया है तथा

1979 से बाद ाहपुर के भाराब के ठेके को हटा दिया जायेगा। परन्तु मुझे बहुत खेाद के साथ सदन को सूचित करना है कि ग्रम पंचायत बाद ाहपूर में वर्श 1979 के लिये भाराब का ठेका पुनः नीलाम कर दिया गया है। इसलिये सरकार को इस प्रकार की अनियमितताओं की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये तथा ' ाराब–बन्दी' को लागू करने के लिये तुरन्त पग उठाने चाहिये। इसी सन्दर्भ में मुझे करनाल जिले से एक दो टैलीग्राम मिले है वहां पर भी तीन जगह भाराब के ठेके नीलाम हुये है।

श्री अध्यक्षः आपने जो काल अटैन ान मो ान दिया है,वही पढ़े । करनाल के बारे में आपके काल अटैन ान मो ान में कुछ नही है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, यह भी इसी से सम्बन्धित है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि भाराब बन्दी के लिय`सरकार ज्यादा सावधानी बरते। जहां से प्रस्तव आ चुके है, वहां पर हर हालत में भाराब के ठेके नही खुलने चाहिये।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं 26 तारीख को ब्यान दूगां–

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय सदन की मेज पर कागज रखेगें।

Irrigaiton and Power Minister (Shri Verender Singh): Sir, I beg to lay on the Table the statement showing loans reised by the Haryana State Electricity Board upto 31-1-79 for which the State Government stood guarantee for repayment thereof under section 66 of the Electricity (Suppl) Act, 1948.

स्वामी आदित्यवे ा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह से हिन्दी पढना जानते है। लेकिन फिर भी वह बार–बार अग्रेंजी में पढते है आप कृपया इनहे हिन्दीमें पढ़ने के लिये कहें।

श्री अध्यक्षः सवामी जी इस बात पर खूब अच्छी तरह से बहस हो चुकी है। मै ंआपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि सदन का आप वक्त जाया न किया करें।

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, इनको जब हिन्दी पढनी आती है तो इन्हे हिन्दी में पढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्षः वह कोई जवाब तो नहीं था, वह तो टेबल पर कागज रखने थे।

वर्श 1979–80 के बजट पर आम चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः अब साल 1979–80 के बजट पर बहस भुरू होगी। कल श्री भाग मल सदन में बोल रहे थे। वे अपनी स्पीच जारी रखेगें।

चौधरी भागमल(सढोरा––अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, कल मैं बजट पर बोल रहा था। उसी के संदर्भ में मै अपनी बात रखने जा रहा हूं। हमारे इस बजट में कुछ प्रावधान किये गये है ताकि हमारे रिसोर्सिज बढ़ाये जाये। मैं कल बता रहा था कि जंगलात भी आमदनी का एक सोर्स है और जंगलात ज्यादातर हमारी ि ावालिक पहाउियों के नीचे वाले इलाके में हे मसलन छछरौली, सढ़ौरा, नाराणगढ़ या कालका। इस एरिये में बहुत सारे जंगलात है। इससे सारी स्टेट को फायदा होता है। जहां जंगलात से हमें फायदा होता है वहां जंगलात में बसने वाले या उसके नजदीक बसने वाले लोगों को बडी तकलीफ है। असल में लोगों को जो कम से कम हमें सुविधायें देनी चाहिये, वे तो उन्हे मिलनी ही चाहिये। जहां पर जंगलात थोडा सा पडौस में है, वहां पर गन्ना की का त होती हैं गन्ने के बारे में वहां पर काफी बहस भी हो चुकी है। हमारी सरकार को यह पता है कि किसानों की इस गन्ने की वजह से क्या दुर्गति हो रही है। जो इलाकामिल के एरिया में पडता है यानि जो तो बौंडिड एरिया हैख वहां पर तो सरकार ने 2 यपया या अढाई रूपया की सबसिडी किसानों की दी है लेकिन जो इलाके बौंडिड एरिया से बाहर है जैसे हमारे इलाके है जिनमें छछरौली, सढोरा ओर बिलासपुर का एरिया है वहां पर

पुराना गन्ना तो तीन रूपये क्विटल के हिसाब से बिकता है ओर जो नया गन्ना हैवह 6 रूपये क्विंटल के हिसाब से बिकता है । वास्तव में अगर देखा जाये तो किसानों को पुराने गन्ने से तिगुना लौस है और नया गन्ना बेचने से आधा लौस है। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि कम से कम 2 या अढ़ाई रूपयो की जो सबसिडी सरकार देती है, वह हमारे इस एरिया के लोगों को ीीमिलनी चाहिये। इसके साथ–2 इस एरिया में बहुत सारी नदियां और नाले हैं बारि ा होती है तो जमीन कट जाती है जिसकी वजह से जो थोडे बहुंत खेत बोये भी जाते है वहां पर भी फसल पूरी नहीं हो सकती।इसके अलावा वहां पर जंगलों में जंगली जानवरभी काफी होते है। वे भी जो उन्होने खेत बोये है खा जाते है। इस तरह से किसान बुरी तरह से पिस रहा है और मजबूर है। इन जंगलात में दो दफायें लगती है। एक तो दफा 5 और दूसरी दफा 4। दफा 5 के तहत जो रिजर्व जंगलात है, वह आते है जिसकी वजह से कोई भी उनमें एन्टरी नहीं कर सकता। उसको जंगलात वाले मेनेटेन करते है। लेकिन दफा 4 के तहत ऐसा किया हुआ है कि जो किसान के खेत है, उसमें जो पेड उगते है उसको उस किसान को काटने के यिले भी आपके जंगलात महकमें से इजाजत लेनी पडती है। जो पेड़ किसान की अपनी जमीन में भी उगते है, उसको भी काटने की उसको इजाजत नहीं होती। अगर फलड की वजह से या किसी दूसरी वजह से उसका मकान गिर जाये और उसे अपनी मकान बनने के लिये लकडी चाहिये और उसके लिये अगर वह किसान अपनी जमीन के अन्दर पैदा हुआ

पेड़ काटना चाहे तो उसके लिये उसको जंगलात के लोगों से इजाजत लेनी पडती है। मैं अफसरों को तो दोश नहीं देता। मैं डिस्ट्रिक्ट लैवल के अफसरों को भी ईमानदार समझता हूं लेकिन जो वहां पर फारेस्ट गार्ड लगे हुये है, उनके बारे में लोगों के दिलों में तरह–तरह की भ्रातियां फैली हुई है। कोई बगैर परमि ान के जंगलात की लकडी काट ले तो फौरन उसका चालान हो जाता है। अगर वह बेचारा एप्लाई करता है तो जब तक 10 प्रति ात उन लोगों को नहीं देता तब तक उसको परमि ान नहीं मिलती। किसान बेचार की जमीन तो कर्ज के नीचे दबी पडी हैं उसने ट्युबवैल वगैरा के लिये कर्जा लिया हुआ है। कोआप्रेटिव सोसाइटियों में जैसे कि लोगों के साथ हुआ है, वह सब आपको पता है कि लोगों को मुफत में कर्ज के नीचे दबाया हुआ है। खा तो कोइ ाअेर ही गया लेकिन उन बेचारो ंको भुगतना पड रहा है। मजबूरन उन्हे देना पड रहा है। अगर वह कर्जा भी देना चाहे तो वह बेचारा अपने पेड वगैरा काट कर दे सकता है मगर ऐसा करने की उसको इजाजत नहीं हैं। इसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग है जो कान्ट्रैक्टर होते है, उनकी डिपार्टमेंट के लोगो से मिलीभगत है।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हूये)

उपाध्यक्ष महोदय, मैने यह देखा है कि हमारे यहां पर बडे–2 ह्यूज जंगलात काटे जा रहे है। अगर कोई किसान अपने खेत में से पेड काटना चाहे तो उसको तो इजाजत नही ओर

ूदसरी तरफ इतने बडे –2 जंगलात मिली भगत से काटे जा रहे है।अगर कोइ किसान काटता है तो उसका तो आप चालान कर देते है।दूसरी तरफ जंगलात के जंगलात कट रहे है, उनको पूछने वालाल कोई नही है। इस इलाके में खैर के पोड कट रहे ळे जोकि बहुत ही ज्यादा तादाद में यहां पर खड़े है । इस इलाके में चर्चा इस बात की है कि यह जो खेर के पेड़ काटे जा रहे है। जरूर इसमें किसी बडे हाई –अप की मिलीभगत है। हो सकता है वह कोई मिनिस्टर ही हो, जिसकी वजह से यह खैर के पेड काटे जा रहे है। यह हमारे वहां आम चर्चा है। उन लोगों को अगर वे जानवर भी पालते ळे तो उनके जानवरों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अगर उनके जानवर कही भूले–भटके से उधर चले जाये ंतो उनका चालान हो जाता है। चालना सही है या गलत इसके लिये उनका यल ऐसा है कि किसी की भी वहां पर सुनवाई नहीं होती। फारेस्ट का गार्ड यह कह दे कि इस आदमी ने यह गलती की है तो जो जुर्माना वह लगा दे उस किसान को देना पडता है और उसकी कोई अपील भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद समझ सकते है कि इन हालात मं उस इलाके की क्या द ा होगी। आप तो उस इलाके में घू कर भी आए है ओर आपको पता है कि उस इलाके में जंगली सियारन ओर दूसरे जंगली जानवर होते है और अगर कोई आदमी जिसकी एक किल्ले जमीन भी है ओर अपनी फसल की हिफाजत के लिये वह उन जंगली जानवरो को मारना चाहता है तो उसको उन जंगली जानवरो को मारने की इजाजत नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब उस

इलाके की एक और समस्या है और वह यह है कि वहां पर नदियां बहुत है। पनी उपर से पडता है और सिंचाई का कोइ इंतजाम नही है। कुछ गहरे नलकूप लगाये जा रहे है ओर कुछ लगे भी है जिससे कि लोगों को सिंचाई के लिये पानी दिया जा सके लेकिन इस काम के लिये भी रिपोर्टें ली जाती है। अगर यह रिपोर्ट आ जाए कि पानी कम है तो नलकूप नहीं लगाये जाते हैं । आपको तो पता होगा कि पीछे एक स्कीम बनाई गई थी कि जो नदियां वहां पर निकलती है उनको रोका जाए ओर बांध बनाकर नदियां निकालकर वाटर सप्लाई की जाये। ऐसा करने से ुसलों को बडा फायदा होगा ओर हमारे जो किसान भाई है। वे बहुत खु ा होगे। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि बांध बनाकर पानी सप्लाई करने की स्कीम को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की कृपा करे जिससे कि वहां के लोगों की तकलीफ दूर हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा इलाका बहुत पिछडा हुआ है और मेरी कांस्टीटयूएंसी में बहुत गांव है। कोई सदस्य कहता है कि मेरी कांस्टीटयूएंसी में चालीस गांव है ओर कोई कहता है कि पचास गांव है लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरी कांस्टीटयूएंसी में अढ़ाई सौ गांव है और वे छोटे–छोटे गांव है और वे स्कैटर्ड गांव है। वहां पर बच्चों के पढने का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां पर सिर्फ पांच गवर्नमेंट हाई स्कूल है ओर बाहर मिडिल स्कूल अगर एक बच्चा हाई स्कूल मं पढनाचाहे तो उसे बीस इक्कीस मील जाना पडता हैं आप अन्दाजा लगा सकते है कि इतनी दूर जाना कोई आसान काम नहीं हैं पांच हाई स्कूल एक लाख डेढ़ लाख आबादी को कैसे फीड कर सकते

है। मैने ऐजुके ान मिनिस्टर साहब से इसका जिक्र किया था ओर उन्होने पूरी हमदर्दी दिखाई थी, ओर वादा किया है कि वहां पर और स्कूल एि जायेगें। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर लडकियां उच्च ि ाक्षा ्रहण कर ही नहीं सकती है। प्राईमरी क्लासिज तक तो वे पढ सकती है लेकिन बाहर जाकर उच्च ि ाक्षा प्राप्त करनाउनके लिये बडा कठिन होता है क्योकि कोई भी अपनर लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहता है। एक तो वह बैकवर्ड इलाका है इसलिये कोई भी अपनी लडकी को घर से बाहर भेजना पसनद नहीं करता है और दूसरे उस इलाके में ऐसी धारणा भी है कि लडकिया घर से बाहर न भेजी जाऐ। मैने पीछे भी प्रार्थना की थी और अब फिर प्रार्थना करता हूं कि इस डिस्पैरिटी को दूर किया जाए और वहां पर अधिक स्कूल खोले जाएं जिससे कि वहां पर लोग आगे बढ़ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर डिस्पैन्सरीज की काफी कमी है। छछरौली, बिलासपुर ओर सढ़ौरा में पी0एच0सीज0 हैं लेकिन वहां पर डाक्टरों की कमी है। किसी पी0एच0सीज0 के पीछे सौ गांव है और किसी पी0एच0सीज0 के पीछे एक सौ पचास गांव है। इतने सारे गांवो को एक पी0एच0सी0 को फीड करना पड़ता हैं वहां पर लेडी डाक्टर्ज की तो बहुत ही कमी है। सिढ़ौरा में तो आज तक लेडी डाक्टर आई ही नहीं है। इन पी0एच0सीज0 की हालत यह है कि कही एक डाक्टर है, कही दो डाक्टर है ओर कहीं पर तीन

डाक्टर्ज है। अगर एक डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसकी जगह कोई नहीं आता है। अगर एक डाक्टर गांव का दौरा करनें चला जाता है तो पी0एच0सी0 में कोई डाक्टर नहीं रहता और जनता को काफी तकलीफ होती है। अगर डाक्टर दौर पर न जाये तो गांव के लोगों को कोई इलाज नहीं मिलता। उस इलाके में कोई आयुर्वेदिक या किसी ओर तरह की डिस्पैन्सरी नहीं है। कुछ अनाड़ी लोग बैठे हुये है जो प्राईवेट इलाज करते हे और उनको कुछ आता जाता नहीं हैं। अगर कोई मर भी जाये तो वे लोग कोई परवाह नहीं करते हैं लेडी डाक्टर न होने से हालत यह है कि अगर कोइ लेडी बीमार हो जाये तो कोई देखने वाला नहीं है। पिछले दिनो लेडीज के तीन केसिज हो गये थे ओर उन तीनों को बाहर ले जाना पडा। बडे दुख की बात है कि तीनों की रास्ते में ही डैथ हो गई थी। इसलिये वहां पर लेडी डाक्टर की बहुत आव कता है। हमारी बहन स्वास्थय मंत्री जी यहां बैठी हुई है मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे उस इलाके की तरफ कुछ ध्यान देने की कृपा करें। सढ़ौरा मे जो डिस्पैन्सरी है उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। वह किसी भी टाइम गिर सकती हैं उसका बरसात मे गिरने का डर रहता है और इस चीज की तरफ मैंने पहले भी सरकार का ध्यान दिलाया था। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर वह बिल्डिंग गिर गई तो कोई आदमी वहां पर मर भी सकता है और वह डिस्पेन्सरी भी खत्म हो जाएगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस बिल्डिंग को वेंकेट कर दिया जाये और उसकी जगह नहई बिल्डिंग बनाई जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, सढौरा में एक्सरे

प्लांट लगा हुआ है लेकिन पता नहीं वह डिफैक्टिव है या वहां पर कोई आप्रेटर नहीं हैख बहुत दिन से बेकार पडा है। अगर कोई ऐक्सरे कराने का छोटा सा भी केस होता है। तो उसको नारायणगढ भेजा जाता है। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है । हमारी सरकार रूरल इंडस्ट्रिलाईजें ान की तरफ काफी ध्यान दे रही है और हमने भी वहां पर इंडस्टरी लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित हिया और बारह केसजि हमने तैयार किये लेकिन वहां पर केवल एक बैंक है और वह है पंजाब ने ानल बैंक। लेकिन यह बैंक लोगों के साथ कोआपरेट नहीं करता है। अगर कोई लोन का केस होता है तो छः छः महीने तक उसका फैसला नही किया जाता और लोगों को लोन सैंक ान नहीं होता। अगर सरकार चाहती है कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान मे तरक्की हो तो मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि मेरे इलाके में बैक की सुविधाये ंबढाई जाये। मेरी खासतौर से इंडस्टरी मिनिसटर से प्रार्थना है कि वहां और बैंक खुलवाने की कृपा करें और उनका डायरेक न दी जाये कि वे जल्दी केस डील करें।

मेरी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि सढ़ौरा में आई0टी0आई0 खोली जाये। अब हालत यह है कि इस इलाके के बच्चों को अम्बाला जाना पडता हैं अगर वहां पर आई0टी0आई0 होगा तो अच्चे अपनेघर पर रहकर ही टैक्नीकल ऐजूके ान हासिल कर सकेगे और उससे कोई डिप्लोमा मे करके कहीं न कही नौकरी हासिल कर सकेगें। सढौरा के अन्दर आई0टी0आई0

खोलने का केस चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी फाईनेलाइज किया जाये । अगर किन्ही हालात की वजह से आई0टी0आई0 खोलना मुमकिन न हो तो गैस्ट क्लासिज सढ़ौरा में भुरू की जा सकती है। ऐसा करने से सौ, दो सौ बच्चों को रोजगार का अवसर मिलेगा और उस इलाके के लोगों को प्रोत्वसाहन मिलेगा ओर इस प्रकार से वहां बच्चे इंडस्ट्रियलाइजे ान स्कीम के अन्दर भाग लेगे और हमारे बच्चों का जो नौकरी की तरफ भागने का रूझान है वह भी कम हो जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मै ंआपका ध्यान हरियाणा मे ला एडं आर्डर की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले 30 सालों मे अम्बाला जिले की पोजी ान ऐसी रही है कि वाहं पर कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई डाका नहीं पडा लेकिन अब एक दो सालों से वहां ला एंड आर्डर की पोजी ान बहुत खराब हो गई है, लोगों की नाजायज तौर पर मारपीट हो रही है, लोग रात के वक्त रास्तों में खडे रहते है ओर लोगों को लूटते एवं मारपीट करते है। जगाधरी रोडपर यह पोजी ान थी कि रात के दो–दो बजे लोग आते जाते थे लेकिन उन को कोई छेड़छाड. नहीं करता था लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, कई कत्ल हुये है और लोग जब रात के वक्त गुजरते है तो उनको लाठियों से पीटा व मारा जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक दो मिसलें देता हूं ।हमारे हल्का में एक आधवदरी नाम धर्म स्थान है, वहां पर एक महन्त रहता था उसके उपर हमला किया गया। एक वहां पर

ब्रह्मचारी था, उसने सिर के उपर कपडा बांधा हुआ था, उस पर भी तलवारों से हमला किया गया, जब तलवार उसके सिर पर मारी गई तो उसके सिर का कपडा फट गया ओर खून बहने लगा ओर वह कपडा अब भी उसके पास रखा हुआ है। वहां पर एक पादरी भी था, वह भी अपनी जगह छोड़कर भाग गया। यह सारी बातें कई बार पेपर्ज में भी आ चुकी है लेकिन फिर भी कोई ऐक ान नहीं लिया गया है। मेरी सरकार से दर्खास्त है कि वह इन बातों की तरफ ध्यान दे और कसूरवार लोगों को सजा दे ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके और वे आरम से अपना जीवन बितासकें।

इससे आगे एक और मिसाल मैं आपको देता हूं यह कोई सात या आठ नवम्बर का वाक्या है। जगाधरी में एक कैल गांव है, वहां पर एकबाबू राम नामक हरिजन था। उसको कत्ल कर दिया गया। इस बारे मे कई बार डैपूटे ान भी सरकार से मिला और हम लोग होम मिनिसटर साहब से भी मिले, कई एम0एम0एज0 भी मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस केस की इंक्वायरी आज तक भी नहीं हुई और जिन लोगो का भाक में नाम लिखवाया गया था, उनको बाद में छोड दिया गया। उन लोगों द्वारा अपनी जमीन गिरवी रखकर 50 हजार रूपये इस केस से छुटकारा पाने के लिये खर्च किये गये थे। अब यह सरकार का ाकम है कि वह इंक्वायरी करे कि वह 50 हजार रूपये किन–किन जगहो पर किन–किन अफसरों पर खर्च किये गये व कहां–2 खर्च कियें गये। इस बारे मे हमने सरकार से प्रार्थना

भी की थी कि यह केस उसी एस0एच0ओ0 के पास ही पडा है। इस केस का अभी तक कुछ नहीं बना है ओर न ही किसी आदमी को वहां से तबदील ही किया गया है। इस कारण से लोगों का फैथ गवर्नमेंट से हट रहा है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे केसिज में सरकार की तरफ से भीघ्र ही इंक्वायरी की जानी चाहिये इसी तरह का एक ओर केस है । रोहतक में होली के दिनों में हिसार रोड पर हरिकि ान नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ ट्यूबवैल के पास सो रहा था, उसी ट्यूबवैल पर उसका अपना मकान हे, वहां कुछ आदमियों ने उसका दरवाजा खटखटाया ओर रात भर उस आदमी को पीटा ओर उसकी नवविवाहिता बीवी केसाथ व्यभिचार किया। फिर उसके बाद बावेला मचा और वहां के एस0वी0 ने कुछ कार्यवाही की। एक ओर नवाजस नाम का गांव रोहतक के पास है। वहां पर भी भाराब पीकर हरिजनों के उपर हमला किया गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि गरीब हरिजनों और दूसरे लोगों पर अत्याचार हो रहा हैं सरकार को इस तरफ पुरा ध्यान देना चाहिये। एक तरफ तो हम किसान और हरिजन भाइयों के लिये सब कुछ करने जा रहे है ओर दूसरी तरफ उन पर अत्याचार हो रहा है। सरकार अगर इस मामले में चुप्पी बरतेगी तो लोगें मे उसके प्रति असंन्तोश की भावना जागेगी और लोग दुखी होगे, लोगों का रहना मु कल हो जायेगा। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि ला एंड आर्डर की स्थिति में सुधार आये।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात बडी खु ी की है, जो हमारी सरकार ने की है वह यह है कि एच0सी0एस0(एग्जैक्टिव) और जुडि ाअल दोनों का ग्रेड एक बराबर कर दिया है। सरकार का यह सराहनीय कदम है। हमारी हरियाणा की हकूमत का इन्ही बड़े–बड़े एच0सी0एस0 और आई0ए0एस0 के कैडर के लोगों के उपरा सारा दारोमदार है। यह लोग तो प्र ासन की क्रीम होते है, वे बाहर से चार–चार पांच–पांच साल का कोर्स करके आते है ओर जब वे यहां आते है तो उन्हे कुछ नहीं मिलता है और वे लोग मायूस हो जाते है। अच्छे गैड नहीं मिलते है तभी वे लोग बाहर के मुल्कों में भागते है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे एसद्धडी0ओ0 है उसका 1963 में 250 रूपये का ग्रेड था और 1968 में इम्प्रूव होकर 350–800 का हुआ ओर उसके बाद 1979 में 400–1100 का ग्रेड हो गया है लेकिन इसमें कोई स्पे ाल ग्रेड नहीं है। एस0ई0 का ग्रेड केवल 700–1300 का ही है जबकि एच0सी0एस0 का भी 700–1300 का है। इसलिये सरकार को कोई स्पे ाल ग्रैड देने चाहिये। मै ंआपको बताता हूं कि अंग्रेजो कके वक्त में डी0सी0 सिविल सर्जिन, एक्सीअन वर्गैरह सभी एट पार हुआ करते थे ओर कोई एक दूसरे के काम मे दखल नहीं देता था ओर आज हालात यह है कि हरेक अफसर का रिकार्ड डी0सी0 ही लिखता है ओर उसकी मर्ज के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक नान टैक्नीकल आदमी एक टैक्नीकल आदमी की सी0आर0 लिखे यह कोई उचित प्रतीत नहीं होता। इससे लोगों के दिलों मेंबडी हार्ट बरनिंग है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। मैने

पीछे भी कहा है कि जो हमारे इंजीनियर्स है, डाक्टर्ज है, उन लोगों को पूरी सहूयिते ओर ग्रेडज नहीं मिलते है जिनके कारण उनहे बडी हार्ट बरनिंग है। इसी कारण से वे बाहर भागते है। अतः सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। अभी सरकार ने यह किया है कि एस0पी0 की सी0आर0 डी0सी नहीं लिखेगा और एस0पी0 अपने सबौर्डीनेट की रिपोर्ट स्वयं लिखेगा। यह एक अच्छी ट्रेडी न है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हरे अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने अपनें विभाग के सबौर्डीनेटस की सी0आर0 लिखे।

श्री उपाध्यक्षः भाग मल जी, काफी समय आपको बोलते हुये हो गया है अब आप वांइड अप करे।

चौधरी भाग मलः डिप्टी स्पीकर साहब, मे ंआपको कुछ और कैटैगरीज के ग्रेड की बाबत भी बताना चाहता हूं। 1963 में डाक्टर्ज का ग्रेड 250 रूपये था 1968 मै 350–800 हो गया ओर अब 1979 में 400–100 का हो गया है ओर असिसटैन्ट डायरेक्टर का 850–1300 का ग्रेड हैख्, पर इन सभी के लिये कोई सिलेक ान ग्रेड नहीं है। ऐडी ानल डायरेक्टर का 1800–2000 का है ओर इस तरह से आयुर्वेदिक डाक्टर्ज का 350–900 का ग्रेड है। इसी प्रकार एजुके ान में प्रिंसीपल का 1100–1800, लेक्चरार्ज का 700–1100 का है , बी0एड0 टीचर्ज का 220–400 जे0बी0टी0 टीचर्ज का 125–250 का ग्रेड है जबकि आई0टी0आई0 प्रिंसीपल

का केवल 350–900 का ग्रेड है जोकि दूसरे प्रिसीपलों से बहुत कम है इस तरह से लोगों को बडी हार्ट बरनिंग होती है।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आई0टी0आई0 के लैक्चरर्ज होते है वे टैक्नीकल हैन्ड होते है ओर वह एक बैंक बोन की तरह होते हे, उन के ग्रेड दूसरों के मुकाबले में सरकार की तरफ से बहुत थोडे रखे गये है। इसी प्रकार एक सेक्रटेरियट का असिस्टेन्ट है उसका ग्रेड 225–500 का है ओर एक डायरैक्टोरेट में काम करने वाले आस्सिटेन्ट को 160–400 का ग्रेड दिया जाता है। ऐसी जो डिस्पैरिटी है वह उन लोगो ंको खलती है जिनके ग्रेड कम है। मैं समझता हूं कि यह बडी बुरी बात है क्यो न सभी ग्रेड एक जैसे हो। जहां क्लार्को की बात आतीहै वहां पर भी डिस्पैरिटी की बात आ जाती है। दफतरो मे ग्रेड और है और जो क्लर्क कारपोरे ांज में लगे ंहुये है उनके ग्रेड और है और उन को साथ में बोनस भी मिलता है।

श्री उपाध्यक्षः भाग मल जी, आप दो मिनट में खत्म कीजिये।

11.00 बजे।

चौधरी भाग मलः इसी तरह से क्लास फोर की तो बात ही न पूछो। डायरैक्टोरेट में तो इनका स्केल 70–95 का है ंऔर सैक्रेटेरियेट में 80–120 का है। क्लास फोर वहीं है, वहीं काम इनका है और वही उनका है। आप देखें कि हमारे गवर्नमेंट

मुलाजिम जो गवर्नमेंट को चलाते है उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है ंमेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस डिस्पैरिटी को बहुत जल्द दूर करे वरना ऐसा न हो जैसे किसी ने कहा है कि–

वक्त पर काफी है कतरा आबे खु ा हगांम का,

जल गये खेत तब बरसा तो किस काम का।

ऐसा न हो कि ये लोग धीरे–2 गिरते जायें और कल को गवर्नमेंट के लिये सिरदर्दी पैदा न कर दें। इन भाब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

कवंर राम पाल सिंह(घरोंडा): उपाध्यक्ष महोदयख 1979–80 के बजट ऐस्टीमेटस पर चर्चा चल रही है मैं भी इस विशय में अपने विचार रखने के लिये खडा हुआ हूं। सबसे पहले जब हम इसके दूसरे पैरे को पढते हे तो हमें यह याद दिलाता है कि जब से जनता सरकार पावर में आइर्द तब से ही भगवान इसके उपर कूर रहा। सरकार बनते ही स्टेट केअन्दर फलड आयें ओर इन फल्डों से अभी सरकार छुटकारा भी न कर पाई थी, यानि लोगो ंको अभी पूरी राहत नहीं दे पाई थी कि ओलावृश्टि हो गई। यही हाल इस वर्श भी हुआ। यह कुदरती आफतें नई बात नहीं है कि ये जनता सरकार बनने के बाद ही आई है, यह पहले भी आती रही है। लेकिन मुझ ेदुख इस बात का हो रहा है कि हमारे अपोजी ान के भाई जिनमें से दो–तीन तो बड़े सीजंड

पोलिटि ायंज है उन्हेने गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुये सिवाये सरकार के खिलाफ चर्चा करने के कुछ नहीं किया। उनको चाहिये था कि सरकार ने जो भले काम किये है , लोगों को राहत दी है, लोगो का दुख दूर करने की कोि ा ा की है उसकी वे तारीफ करते। लेकिन दुख की बात है कि उन्होने एक लफज भी ऐसा नहीं कहा। वे कहते है कि जनता सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं अपोजी ान के भाइयों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने फल्ड रिलीफ दी और फल्ड से घिरे हुये लोगों को बताना चाहता हूं कि सराकर ने फल्ड रिलीफ दी और फल्ड से घिरे हुये लोगों को हवाई जहाज से रोटियां दी, मकानो के लिये कर्जा दिलवाया। क्या यह छोआ काम था? इतना ही नहीं इन कामों के साथ–साथ डिवैलपमेंट का काम भी चलता रहा। इन कामों के लिये सरकार बधाई की पात्र है और ऐसे काम करने के बाद हरियाणा का कौन आदमी ऐसा है जो सरकार को बधाई न दे ओर सरकार के कामों को अच्छा न कहे। यहीं नही सरकार ने उस वक्त जो ड्रेनों का काम था वह भी अपने हाथ लिया। उजीना ड्रेन जैसा काम सरकार ने अपने हाथ में लेकर उसे जल्द से जल्द पूरा करवाया। डिप्टी स्पीकर साहिब, गुडगांव जिला अपका अपना जिला है और आपको मालूम है कि वहां पर पिछले साल से कितने काम हुये है। पिछले साल जिस जमीन पर पानी ही पानी नजर आता था इस साल वहां हरी भरी खेतियां दिखाई देती है । इसका कारण यह है कि सरकार ने तुरन्त कदम उठाये और ड्रेनों का काम अपने हाथ में लिया हैं यही नही जमुना के आस–पास पिछले साल भी और इस

साल भी नुक्सान हुआ है लेकिन सरकार ने वह काम भी अपने हाथ में लिया हैं लेकिन दुख इस बात का है ंकि जमुना ने अपना बहाव बदल लिया है और इस वजह से कुछ एरिया ऐसा हैजो उसकी लपेट में आ जाता है। बदकिस्मती से वह इलाका मेरे हल्के में ही पउता हैं इस बारे में मैं सरकार को भी कई बार कह चुका हूं और इंजीनियर्ज को भी मौके पर हालत दिखा दी है लेकिन इंजीनियर्ज ने अपनी दिक्कत यह बताई कि यह मामला जमुना कमेटी के पास है। अगर यह मामला जमना कमेटी के पास ही रहा तो मुझे खद ा है कि अगर इस साल भी जमुना में ओर पानी आ गया तो मेरे हल्के का भायद ही कोई गांव बच सकेगा। इस साल भी जमुना के प्रकोप ने 7–8 गांवों की आबादी को बिल्कुल तबाह कर दिया। इस समय मिनिस्टर साहब तो बैठे नहीं है भायद इंजीनियर साहब बैठे होगें । उनसे मैं यह बात कहूंगा कि मेरे हल्के का केस इस साल हाथ में जरूर जाये क्योकि यू0पी0 की तरफ मेरे हल्के के सामने पक्का बांध बना हुआ है ओर अगर पानी आ गया तो वह बहाब की तरफ ही जायेगा, बांध की तरफ नहीं जायेगा। उसका ह ार यह होगा कि जमुना का टोटल बहाव इधर हो जायेगा ओर कमसे कम पांच सौ गांवों के करीब न तो जमीन मिलेगी और न वाहां पर कोई बसने वालामिलेगा। जब हरियाणा का अपना फलड कन्ट्रोल बोर्ड है तो वह मोके पर जाकर स्थिति को देखे कि वाकई यह डेंजरस पंवायट हैं अगर यह मामला जमना कमेटी के पास पडा रहा तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब का भी इलाका नहीं बच सकेगा। इसलिये

मैं फाइनैंस मिनिसटर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले को फलड कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में लाकर इस पर जल्द से जल्द काम भ्रुरू करवायें। अगर देरी होगई तो बहुत बुरा हाल होगा। काम भ्रुरू करवाने के लिये इस वक्त तो आपको लेबर भी मिल सकती है। लेकिन जब फसल की कटाई का वक्त आ जाएगा तब लेबर भी मिल सकती है लेकिन जब फसल की कटाई क वक्त आ जायेगा तब लेबर भी नहीं मिलेगी। इसलिये फलड कंट्रोल बोर्ड की मीटिग बुजा कर इसका जल्दी फैसला किया जाये नही ंतो करनाल का काफी से ज्यादा एरिया तबाह हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर आगे इंडस्टरी के बारे में कहा गया हैं इंडस्टरी के बारे में मैं अधिक समय न लेकर दो–तीन बातें ही करना चाहता हूं। सब से पहले मैं सरकार को बधाई दूंगा कि उसने जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान का प्लान बनाया है ओर लघु उद्योग का प्लान बनाया है यह बहुत अच्छा प्लान है। इससे दो फायदे होगें। एक तो गांवों में जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिलेगा दूसरे जो लोग फसल की कटाई के बाद बेकार रहते है उनको काम मिलेगा। लेकिन मैं इसमें एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि ये उद्योग जे लगाये जा रहे है और इनसे जो माल तैयार होता है उसकी मार्किटिंग की प्रौब्लम आती है इसलिये यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये कि वह खुद उस माल को बेचने की व्यवस्था करें अगर उनके माल की फरोखत का इन्तजाम नहीं होगा तो यह उद्योग कामयाब नहीं हो सकेगें मैं

चाहूंगा कि सरकार इसका कोई न कोइ प्रबन्ध करे औरन इसहाउस में फैसला हो कि लघु उघोग का सारा माल चाहे कंज्यूमर्ज स्टोर्ज के जरिये या किसी और जरिये से सरकार खरीदेगी। मुझे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर उद्योग विभाग का एक हैड होता है। हमारे करनाल में इस बारे में ज्यादती हो रही है। मुझे पता चला है कि इंडस्टरी का करनाल का हैड क्वार्टर बदलने के आर्डर हो गये है। इसको पानीपत में बदलने के आर्डर हुये है। अगर करनाल से यह आफिस ि ाफट हो जायेगा तो यह ज्यादती होगी। पानीपत में 126 गांव हे जबकि करनाल में 471 गांव पड़ते है। पानीपत में तो आलरैडी उद्योग लगे हुये है और वे डिवैल्पड हैं । अगर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर करनाल में होगा तो करनाल के लोगों को लघु उद्योग लगाने का प्रेात्साहन मिलेगा और वे उद्योग के बारे में आराम से अधिकारियो से कंटैक्ट कर सकते है। उपाध्यक्ष महोदय हैड क्वार्टर घरौंडा में नहीं चाहिये, करनाल में चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत एक जनरल मैनेजर होता है और चार पांच मैनेजर होते है। पानीपत में मैनेजर का आफिस खोल दे ंतो बडी आसानी से काम चल सकता है। अगर उसे वहां किसी प्रकार की दिक्कत हो, तकलीफ हो तो वह दो तीन दिन मुकर्रर करे ले और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर रह कर काम कर सकता है। मैं इंडस्टरी मिनिस्टर और फाइनैंस मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें। इस बजठ में ऐग्रीकल्चर का जिक्र आया है कि पिछले साल की बजाये इससाल एग्रीकल्चर की बढोतरी हुई है यह बडी

खु ी की बात है। यह भी खु ी की बात है कि इस दफा ओलों से जो फसल खराब हुई है उसके लिये सरकार ने एक सौ, दोसौ, तीन सौ रूपये तक की लोगों को ग्रांट दी है और दी जायेगी ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इस साल लोंगों को फर्टीलाइजर की भी कमी रही है। लोंगों को फर्टीलाइजर खरीदना मु कल हो गया है। जब सरकार सग्रीकल्चर पर इतना पैसवा लगाना चाहती है और एग्रीक्लचर को प्रोत्साहन देना चाहती है तो इस में जो भी चीजें प्रयोग में लाई जाती है उनका सरकार प्रबन्धस करे। पिछले दिनों ऐ सवाल आया था उसमें। पूछा गया था कि हैफेड से जो खाद दिया जाता है वह स्टेट में लोगों को वेट में थोड़ा क्यों दिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब प्राइवेट डीलर्ज हैफेड वालों से मिले रहते है और वे वहां से खाद ले आते है। किसानों को फर्टीलाइजर की जल्दी जरूरत होती है और वे प्राइवेट डीलर भी हैफेड से खाद खरीद लेता है। हकीकत यह है कि हैफेड से ही कोई कट्टा पूरा नहीं उठाया जाता। भाकर करने से भी कुछ नहीं बनता क्योंकि किसान को फर्टीलाइजर की जरूरत होती है ते वह डीलर से उसी प्रकार ले लेता है। जिस वक्त कट्टे रिफिल किये जाते है उसी वक्त ही हेराफेरी की जाती हैं किसान को पूरे पैसे लगा कर भी खाद वजन में पूरा नहीं मिलात। नुकसान तो किसान को हो रहा है। एग्रीकल्चर के अन्तर्गत ही इरीगे ान भी आ जाता है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। सरकार इरीगे ान के लिये इतना पैसा खर्च करने जा रही है। नहरों की लाइनिंग की जायेगी लेकिन वाटर कोर्सिज का खर्चा

किसान पर पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मान सकता हूं कि नहरों और माइनरों की लाइलिंग करने से पानी बचता है क्यांकि इनको पक्का करने से सीपेज नहीं होगी लेकिन मैं कह सकता हूं कि वाटर कोर्सिज जिनको खाल कहते है , किसान इस का खर्च नहीं देसकेगा। इसका कारण यह है कि पहले तो किसान लाइनिंग का खर्चा देगा फिर उसके साथ–2 रिपेय कर काम भुरू हो जायेगा वह भी उसको देना पडेगा। इस तरह तो यह किसान पर एक परमानैंट टैक्स हो जायेगा, यह अभी के लिये नहीं है हमें ाा के लिये टैक्स हो जायेगा। अगर आप सग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना चाहते है तो नहरों की लाइजिंग कर दें परन्तु वाटर कोर्सिज की लाइनिंग न करें। आप किसान पर रहम करे। अगर पक्का खाल लीक रकने लग जाये तो किसान को बहुत हानि होगी, कच्चा खाल अगर लीक करने लगेगा तो उसको वह मिट्टी से बन्द कर देगा और वह पानी उसके खेत में नहीं जायेगा। कच्चे खालों से कुछ ही पानी खराब होगा बाकी तो खेतों में लगेगा। पक्का होने से पानी भी लीकेज से ज्यादा निकल जाएगा और लोगों की फसल को भी नुकसान होगा। पक्के खालें में अगर सीपेज होगी तो किसान डिपार्टमेंट को लिखेगा। डिपार्टमेंट वाले आकर देखेगें, फिर उसकी वे रिपेयर करेगें। इतेन समय जो पानी खेंतों में खडा रहेगा वह फसल को बिल्कुल तबाह कर देगा। जिसका खेत है वह तो बिल्कुल खराब हो जायेगा। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि खालें पक्का करने की प्रोजोजल को ड्रौप किया जाये। इससे खास फर्क पडने वाला नहीं हैं माइनर को बे ाक

पक्का करें परन्तु पवके खालों से पानी तो वेस्ट जायेगा ही, साथ ही फसल भी खराब होगी। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में एस0वाई0एल0 योजना पर और भी जयादा पैसा खर्च करने के बारे मैं कहा गया है। मैं तो कहूंगा कि जब तक पंजाब में चैनल नहीं बन जाती तब तक एस.वाई.एल. योजना पर पैसा खर्च करना पैसे की वेस्टेज ह। अब तो इसके बनाने पर पैसा लग रहा है, फिर रिपेयर पर भी खर्च होगा। जो पैसा हम खर्च करेगें उसका इंट्रैस्ट बढता जायेगा, जब तक फैसला नहीं होता खर्चा बढता ही जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इसका फैसला भी होगा कि नहीं। आज भी मैने अखबार में पढा था कि पंजाब नोटिस दे रहा है, जो भी इस योजना मे हिस्सेदार है, उन्हे नोटिस दे रहे है। इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब गवर्नमेंट हमारी बातों में आकर चैनल नहीं बना कर देगी। हमारी सरकार को इस बारे मेंसोचना होगा कि हमें क्या स्टैप लेने हैं। स्वामी अग्निवे ा जी ने भी इसका जिक किया था कि अगर हमें एस0वाई0एल0 से पानी लेना है तो स्ट्रांग स्टैप उठाने होगें जिससे हम सैंटर से भी कह सकें कि हमें पंजाब से पानी लेना है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि जब तक पंजाब वाले चैलन नहीं बना लेते एस0वाई0एल0 पर पैसा वेस्ट न किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के लोग मुह बा करके प्यासे की तरह से देख रहे है। हरियाणा की जमीन प्यासी है वह आज पानी की इंतजार में हैं इस लिये सरकार को जल्द से जल्द

पानी का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वह पानी किसान की खेती को मिले खेती हरी भरी हो, पैदावार ज्यादा हो। हरियाणा को पानी न मिलने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा हैं मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह बहुत गम्भीरता के साथ सोचे कि जब तक पंजाब के साथ फसला न हो जाए तब तक सारे डिवेल्पमेंट के काम बन्द करके सारा पैसा पानी के प्रबन्ध करने के लिये लगा दे और मै समझता हूं कि ऐसा करने से किसी को भी एतराज नहीं होगा अब तक हरियाणा में पजांब से पानी लेने के लिये जितनी नहरें बनाई गई है, पंजाब द्वारा अपने इलाके में नहर न बनाने के कारण वे बेकार पडी है और हरियाणा ने जितना पैसा अपनी नहरो ंपर खर्च किया है वह वेस्ट जा रहा है।

ऐकनीमल हस्बेंडरी के बारे में इसके अन्दर जिक आया है मुझे इस बात की खु ी है कि हरियाणा सरकार ऐनीमल हस्बैंडरी की तरफ ध्यान दे रही है। यह ठीक है कि हम हैल्थ डिपार्टमेंट से मांग करते है कि प ुओं के हस्पताल होने चाहिये, रूरल डिस्पेंसरीज होनी चाहिये। लेकिन मै यह समझता हूं कि किसान का जो प ुधन है वह सबसे बडा धन है। मगर होता यह है कि प ु यदि बीमार हो जाये तो 10–10 किलोमीटर के एरिये मे कोई डाक्टर देखने वाला नहीं है। किसानों के लिये बड़ी मु कल होती है कि प ु को हस्पताल तक कैसे ले जाए। अगर कोई मनुश्य बीमार हो जाता है उसको तो साईकिल से, तांगे से, बैलगाडी से या जीप या और किसी साधन से हस्पताल तक ले

जाया जा सकता है लेकिन प ु को हस्पताल तक नहीं ले जाया जा सकता है और डाक्टर को वहां लाया नहीं जा सकता। बेचार प ु तड़फ–2 कर मर जाता है जो कि किसान का बहुत बड़ा धन है। उसके बगैर वह खेती भी नहीं कर सकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 3–3 मील के एरिया के अन्दर रूरल डिस्पैंसरीज का होना बहुत ही आव यक है। किसानों का तो प ु ही धन है अगर उनका खेती के टाईम पर एक बैल मर जाता है तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह दूसरा कोई बैल खरीद सके। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना कंरूगा कि इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा डिस्पैंारीज खोली जाएं।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वांइड–अप कीजिये।

कंवर रामपाल सिहः उपाध्यक्ष महोदय, आज ही पहले दिन मुझे बोलने का समय मिला है। कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में आज ही एक सवाल आया थां उसमें यह कहा गया था कि कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के अन्दर लोग 1.90 करोड रूपये खा गये है। लेकिन जब हम बजट को देखते है तो वह घाअे का बजट पे ा किया गया हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करात हूं कि अगर यह 1.90 करोड़ रूपये उन लोगों से वसूल कर लिये जाएं तो इन किसानों के उपर टैक्स लगाने की कोई आव यकता नही है। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: No interruptions please.

कंवर रामपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, पंचायतों के बारे में यहां बराबर जिक्र आया है और मेरे एक भाई चौधरी उदय सिंह दलाल ने कहा कि पंचायतों के लिये एक कमेटी बनाई हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो सरकार को यह फैसला करना होगा कि क्या वह उस कमेटी की जो सिफारि ों आएंगी उनको मानेगी? मुझे तो नजर नहीं आता कि सरकार मानेगी। उसके कई कारण है एक तो यह है कि चंडीगढ़ के हरियाणा के सैकेटेरिएट की पावर्ज जिला हैडक्वार्टर को चली जाएंगी इसलिये मुझे यह अन्दे ाा हो रहा है कि सरकार कमेटी की सिफारि ा नहीं मानेगी।। जब अ ोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और अगर उस कमेटी की रिपार्ट को मान लिया है तो भाायद चण्डीगढ के काम वहीं पर हो जाएगें क्योंकि रिपोर्ट के अन्दर जिला परिशद के चेयरमैन और ब्लाक समिति के पंचों ओर सरंपाचों को इतनी पावर्ज दी जा रही है कि किसी को यहां आने की आव यकता नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि यदि सरकार इस बात के लिये तैयार है तो ठीक है वह रिपोर्ट आ जाएगी उसको एक्सैप्ट करें और उसको लागू करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अगर हरियाणा इस काम के अन्दर पहल करता है तो सबसे पहले हरियाणा को यह श्रेय जाएगा। उसको ठीक ढंग से चलाने के लिये हरियाणा सबसे पहले अग्रसर होगा और यह हरियाणा के लिये भाबासी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में मेरे भाई चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब, श्री सुरेन्द्र सिंह जी ने एकसवाल के जवाब में बडे प्यारे–प्यारे भाब्दों में ंयह कहा कि

हमारी बसों की आयु 8 साल है इसलिये बसों की आयु जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम उन बसों का चलाएंगें। वह इस समय हाउस में नहीं बैठे हूये है लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय के जरिये अपने भाई सुरेन्द्र सिंह से यह जानना चाहूंगा कि यह 8 साल की आयु कब से भाुरू की गई है? क्या यह जनता सरकार के आने के बाद हुई है या उससे पहले हुई है? मैं पूछना चाहूंगा कि जनता सरकार के आने के बाद क्या बासेां के अन्दर कुछ अच्छा मैंटीरियल लगने लग गया है जिसकी वजह से उनकी 8 साल आयु कर दी गई है? एक दिन बोलते हूये मेरे भाई पोहलू साहब ने कहा था कि यह तो जेल से माफी मांग करके आया ह। मैं भाई पोहलू साहब को इस बात के लिये चैलेन्ज करता हूं कि यह इसको साबित कर दें कि मैं माफी मांग करके आया था तो मैं मैबरि ाप से भी और पोलिटिक्स से भी इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो मेरे भाई पोहलू इस बात के लिये तैयार हो जांए। एक दिन मेरे भाई पोहलू साहब कैथल डिपों के बारे में बहुत भाोर मचा रहे थ। एक तरफ तो हमारे चीफ पार्लियामेटंरी सैक्रेटरी साहब नू पूछा तो उन्होने कहा कि फलां मेक की वहां पर ज्यादा बसें है उनकी टूट–फूट ठीक करवाने में जयादा खर्चा आता है लेकिन इन्कवायरी यह बता रही है कि वहां जो माल आता था जैसे एक्सल, फिल्टर और दूसरी चीजें वह सब की सब वहांसे उठा उइा करके करनाल में बेची गई। अम्बाला मेंबेची गई और जीन्द में बेची गई। एक–एक पुर्जे की कीमत 1400 रूपये है उसको 800 के अन्दर करनाल में बेचा है और इस सब का दोश स्टोर के इन्चार्ज के

सिर पर लादा गयाहैं जनरल मैनेजर अपनी जिम्मेवारी नहं लेता। यदि वह जिम्मेवारी नहीं लेता तो उसका स्टोर के अन्दर बैठने का क्या काम है। जबकि वह यह नहीं ंदेख सकता कि स्टोर के अन्द से क्या चीज चोरी हुई है। इसका कारण मैं बताता हूं । उस स्टोर का जो इंचार्ज है वह जनरल मैंनेजर का रि तेदार है। उसके थ्रू यह सारा घपला हुआ है (विघन तथा भाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से बेचे हुये ऐक्सल करनाल से बरामद हुये है। छोटै मुलाजिमों के खिलाफ तो ऐक ान होजात है लेकिन बड़े बड़े अफसर रास्ता काट लेते है, उनको कोई पूछता नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए पवांयट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, उस जी0एम0 को दोबारा बहाल न किया जाये। रामपाल जी जो कह रहे है, ठीक कह रहे है। (व्यवधान)

कंवर रामपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सरकार ने बस की 8 साल की अवधि कर दी है और दूसरी तरफ बसों की हालत यह है कि वे सडकों पर खडी रहती है, रोजाना ब्रेकडाउन होते रहते है। अगर आपने 8 साल की अवधि रखनी है तो रहने दीजिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि आयु का हिसाब नहीं लगाना चाहिये, आयु 6 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती हे और 10 साल भी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भार्त यह है कि वैहिकल सडक पर चलने केक काबिल होना चाहिये। अगर 6 साल की अवधि से पहले ही कोई

बस इतनी खराब हो जाये कि वह सडक पर चलने के काबिल न हो तो उस बासव को फौरन कंउम कर देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुके ान के बारे में कहना चाहता हूं। आज हमारे एजुके ान मिनिस्टर साहब ने एक बात कही कि वे मानते है कि एजुके ान का स्टेंडर्ड नीचे गिरा है। बडी अच्छी बात है, यह सरकार नेकनीयती से हर बात को लेती है, असलीयत को स्वीकार करने में कोई हिचचिाहट नहीं होनी चाहिये। यह खु ी की बात है। लेकिन एजुके ान का स्टैंडर्ड नीचे गिरने का क्या कारण है? जहां तक मैं समझता हूं, इसका सबसे बडा कारण है सिलेबस की भरमार। प्राईमरी क्लास में इतना सिलेबस लगा दिया है कि बच्चे के उपर बहुत बोझा बढ गया है। नन्ही बुद्धि वाला बच्चा अपना बसता उठाकर स्कूल तक नहीं जा सकता। पांच साल के बच्चे की बुद्धि इतनी ही हो सकती है कि वह छोटा सा कायछा पढ ले, 100 तक गिनती याद कर ले, लेकिन सिलेबस बहुत बडा है कि उसके उपर पांच–पांच किताबें लाद दी जाती है। कई क्लासिज बना दी है, नरसरी कलास, प्री–नर्सरी क्लास, पहली क्लास और तीन–तीन, चार–चार साल इन क्लासों में लगा देते है और परिणाम यह होता है कि कोर्स बढ़ता जाता है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि अध्यापकों की रोज–बरोज तबदीली कीजाती है। अध्यापकों की बार बाद तब्दीली करना एजुके ान को खराब करना है इसलिये इसकी जिम्मेवारी किसी पर नही आती। बच्चें की पढाई ठीक क्यों नहीं है, इसका

उत्तरदायी कौन है, कोई अध्यापक नहीं कहेगा कि मैं जिम्मेवार हूं क्योकि उनकी रोज बरोज तबदीलियां होती रहती है। तीसरा कारण है टैक्नीकल एजुके ान न होना। जैन साहब बैठे है, वे इस बात को नोट कर ले कि घरौंडा के पास कोड़ा गांव है। चार साल पहले उस गांव की पंचायत ने एक रैजोल्यू ान पास करके भेजा था कि यहां पर आई0टी0आई0 का एक सैंटर खोला जाए। लेकिन आई0टी0आई0 सैन्टर तो क्या खोलना था उसकी जगह भौडज बनाकर लघु उद्योग खोलने के लिये किराये पर दे दिये है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंअ को लघु उ़ोग नहीं बल्कि आई0टी0आई0 का सैंटर खोलना चाहिये था। अगर जैन साहब लघु उद्योग की स्कीम वहां पर चालू करना चाहते है तो बच्चों को ट्रेंनिग देने के लिये उन भौड्स का इस्तेमाल किया जाये ताकि बच्चे लघु–उद्योग की ट्रेंनिग ले कर कहीं भी अपना उद्योग खोल सके। इसलिये सरकारसे प्रार्थना है कि वहां पर आई0टी0आई0 का सैंटर खोला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टैक्सज की आइटम पर आता हूं। यह बजट स्पीच के आखिर में दी गई है। सबसे पहले कुछ राहतों का जिक्र किया गया है। सेल्ज टैक्स के प्रोसीजर को आसान बनाने के लिये सरकार एक कमेटी बनाना चाहती है। जैन साहब बडे प्रोमिनैंट लाईयर रहे है और मैं भी वकील हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सेल्ज टैक्स की डैफिनी न क्या है। सेल्ज टैक्स उससे लेना चाहिये जो कोई चीज सेल कर रहा हो।

अगर सरकार सेल करने वाले पर टैक्स नहीं लगा सकती बल्कि परचेज करने वाले पर लगाती है , फिर तो इस टैक्स का नाम परचेज टैक्स रखा जाये, सेल्ज टैक्स नाम नहीं होना चाहिये। क्योकि यह टैक्स परचेजर से लिया जाता है इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसका नाम बदल पकर परचेज टैक्स रख दिया जाए। इस बात पर कई बार झगड़े हो जाते है क्योकि परचेज करने वाला कहता है कि मैं तो परचेज कर रहा हूं, मैं सेल्ज टैक्स क्यो दूं?

चौधरी हरस्वरूप बूराः नाम बदलने से कंज्यूमर पर से बोझ नहीं हटेगा। नाम बदलने की बात न कहें, सेल्ज टैक्स दुकानदार पर पड़े, यह बात कह दें।

कंवर रामपाल सिंहः कहा तो मैंने वही है, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार कम से कम उसका नाम परचेज टैक्स रख दे।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वाइंड–अप कीजिये, आपका टाईम हो गया है।

कंवर रामपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैने बहुत कुछ कहना है। मुझे कुछ समय और दीजिये।

श्री उपाध्यक्षः मै आपको दो मिनट का समय देता हूं। आप दो मिनट मे अपनी बात खत्म कर दें।

कवंर रामपाल सिंहः दो मिनट नहीं, मैं चार–पांच मिनट और लूंगा। मैं टैकस के बारे में कह रहा था, सरकार ने आबियाना बडा दिया और लैंड होल्डिंग टैक्स पर सरचार्ज बढा दिया, स्टैम्प डयूटी बढ़ा दी और हलवाइयों के उपर टैक्स लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार प्रचार करती है कि सरकार किसान के लिये, मजदूर के लिये, हर वर्ग की भलाई के लिये बहुत कार्य करने जा रही है ताकि हर व्यक्ति अपने पावों पर खडा हो सके। खासतौर पर गांवों मेंबसने वाले गरीब किसानों के लिये बहुत कुछ करने जा रही है क्योंकि वे अपने पांवों पर खडा नीं हो सकते, अपना गूजारा नहीं कर सकते। लेकिन मै ंसरकार को बताना चाहता हूं कि गांवों मे रहने वाले गरीब किसानों की तरह ही भाहरों में भी गरीब किसान है जो अपने पांवों पर खडा नहीं हो सकेते, इनको भी राहत देनी चाहिये लेकिन टैक्स प्रोपोजल देखने से मुझे ऐसा लगता है कि इन किसानों के उपर आबियाना का बोझ बहुत जयादा पड़ेगा। सरकार आबियाना टैक्स बढानें की प्ली यह लेती है कि चूंकि सवा 6 एकड़ के मालिकों पर मालिया माफ कर दिया है इसलिये सवा 6 एकड़ के उपर जमीन रखने वाले किसानों से यह पूरा किया जाये। यानि जो राहत सवा 6 एकड़ के मालिकों को दी गई थी वह सवा 6 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों से पूरी की गई है क्योकि आबियाना के बारे में कहा गया है कि नहरों और माइनर्ज पर लाइनिंग की जा रही है, उनका खर्चा बढ़ रहा है, इसलिये सवा 6 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों पर यह टैक्स लगा दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हुं कि

अगर ऐसा ही करना था तो राहत देने की आव यकता ही क्या थी? अगर गवर्नमेंट ने यही पालिसी बनाई है कि जिस सैक ान को राहत दी जाएगी उसी सैक ान के दूसरे लोगों से वह कमी पूरी की जाएगी तो भाहर वालों को जो टैक्सों मे राहत दी गई है , और टैक्स लगाने की लिमिट 40 हजार से एक लाख और 10 हजार से 25 हजार कर दी गई, इस कमी को भाहर के उन बड़े बड़े लोगों से पूरा क्यों नहीं लिया गया? यह प्रोपोजल क्यों नही दी गई कि इस कमी को बडे लोगों से पूरा किया जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के दिमाग से छोटे किसान और बडे किसान की बात नहीं निकली है। लेकिन इसके दूसरी तरफ छोटै इंडस्ट्रियलिस्टस और बडे इंडस्ट्रियलिस्टस की बात कभी किसी ने नहीं की। इनके उपर इन्कम टैक्स लगा दिया जिन्होने पूरा इन्कम टैक्स कभी दिया ही नहीं इनके दो–दो तीन–तीन खाते चलते है। आप फरीदाबाद में जा कर देखिये, माल तो बनता है हरियाणा में और बिकता है दिल्ली में जाकर,। सारे फरीदाबाद इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स में यही हाल है। मैं हरियाणा सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि कानूनी सलाह लेकर इस बात पर पाबन्दी लगाई जाए और जो इंडस्ट्रियलिस्टस सेल्ज टैक्स बचाने के लिये हरियाणा में बना हुआ माल दिल्ली ले जाकर बेचते है उनको रोका जाये। अगर इस टैक्स को बचाया जाए तो अकेले फरीदाबाद कम्पलैक्स से कम से कम 20 करोड़ रूपया बच सकता है।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): यह बात बजट में रखी हुई है।

कंवर रामपाल सिंहः जब होगा तब देखेगें, यू ं तो बजट में बहुत कुछ लिखा है।

श्री उपाध्यक्षः आप खत्म कीजिये, काफी समय हो गया है।

कंवर रामपाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐडमिनिसट्रे ान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारी टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत खर्च हो रहा हैं हमारी स्टैट में जितनी कारपोरे ांज है उनमें आई0ए0एस0 अफसर लगाये हुये है और जितने हमारे यहां टैक्नीकल डिपार्टमेंटस है उन में भी टैक्नीकल अफसरों को हैड आफ दी डिपार्टमेंट न लगा कर आई0ए0एस0 अफसरों को हैड आफ दी डिपार्टमेंट लगाया हुआ है। इस बारे मे मै सरकार को सजै ान दूंगा कि टैक्नीकल डिपार्टमैंट का टैक्नीकल ही हैड होना चाहिये। आई0ए0एस0 अफसर उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता है लेकिन टैक्नीकल आदमी ए से जैड तक की बात जानता है, उसको सारी चीजों का पता होता है।

डिप्टी स्पीकर साहब हमारी जितनी भी पब्लिक अन्डर–टेकिग्ज है उनमें हमारे साथी मैंबरों को चेयरमैंन लगाया हुआ है। मुझे उन कारपोरे ान्ज का तलख तजुर्बा है क्योंकि कुछ

अर्से तक मैं भी चेयरमैन रहा हूं चेयरमैंन की पावर कुछ नहीं होती हैं चेयरमैन केवल मीटिंग प्रिजाइड करता है और कुछ नहीं कर सकता। चेयरमैन को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलनी चाहिये। अगर उसके हाथ में कोई पावर ही नहीं होगी तो उसका वहां बैठने का क्या लाभ है। वहां पर आई0ए0एस0 अफसर तो एम0डी0 लगा होता है। टोटल पावर उसमें वैस्ट करती है। जो कुछ भी करना होताह उसी ने करना है।

डिप्टी स्पीकर साहब उन कारपोरे ान्ज के बारे में मेरा एक और भी सुझाव है कि वहां पर जो आई0ए0एस0 अफसर लगा हुआ होता है उसको कई बार दूसरे दे ाों में ट्रैनिंग पर भेजा जाता है लेकिन जब वे ट्रेनिंग करके आ जाते है तो उनको वहां पर एम0डी0 के रूप में काम करने नहीं दिया जाता है। उनको उसी वक्त आते ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर किसी अफसर को सरकार के खर्चे से ट्रेनिंग पर भेजा जाता है तो उससे लाभ भी उठाना चाहिये। उससे लाभ उठाने के लिये कम से कम कोई भार्त रखनी चाहिये कि जो एम0डी0 ट्रेनिंग पर जायेगा वह कम से कम तीन साल तक यहां पर काम करेगा। ऐसा करने से कारपोरे ान को भी लाभ हो सकता है और वह दूसरी जगह भी नहीं जा सकेगा। जैन साहब ने भी पब्लिक अन्डरटेकिंग के लिये सुजै ान दी है कि जो पब्लिक अन्डरटेकिंग घाटे में चलेगी उसको बन्द कर दिया जायेगा। लेकिन मैं उनके नोटिस में एक बात और भी लाना चाहता हूं कि कई पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज बिल्कुल

सुपरफअूस है। जैसे एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरे न है, वह लैन्ड रिकलेमे ान का भी काम कर सकती है और कलर, थूड जमीन को भी ठीक कर सकती है। लेकिन इस काम के लिये अलग से लैंड रिक्लेमे ान डिवेल्पमेंट कारर्पोरे ान बनाई हुई है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐसी कारपोरे ान्ज को बन्द कर देना चाहिये।

दूसरे जैसा, कि मैने कहा कि कारपोरे ान्ज के जो चेयरमैन लगाये जाते है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाये। पावर मिलने पर ही वे कारपोरे ान्ज का भला कर सकते है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, आज सै ान में बजट पर बहस चल रही है हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने लैंड होल्डिंग टैक्स 33 परसैंट बढ़ाया है यानि निके पास सात एकड़ से ज्यादा जमीन है उन पर यह टैक्स लगेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के किसानों की इतनी अच्छी हालत नहीं है जितनी जैन साहब सोचते है। उनही किसानों की हालत अच्छी है जिनके पास 19 एकड़ से ज्यादा जीमन है या जो सीजिंग की लिमिट है उससे ज्यादा जमीन है यानि सैकडों एकड जमीन रखे हुय है उनकी हालत अच्छी है। जिन किसानों के पास सिर्फ 19 एकड़ या 19 एकड़ से कम है उन की हालत अच्छी नहीं है। आज किसानों के बच्चें पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिये एक हजार या दो हजार रूपये रि वत देने के लिये जेबों में डाले फिर

रहे है लेकिन उनको वह दो सौ रूपये की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। यह आज किसानों की हालत हो गई है।

चौधरी राम कि ानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य राव दलीप सिंह जी ने यहां पर किसानों का जिक किया कि किसानों के बच्चे दो–दो हजार रूपये रि वत देने के लिये जेबों मे डाल कर घूम रहे है लेकिन उनको भर्ती नहीं यिका जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि कोई आदमी किसी को रि वत लेते हुये या देते हूये पकडवायेगा तो उसको पांच सौ रूपये इनाम दिया जायगयेा, तो राव साहब इस बात को मुख्यमंत्री जी के नोटिस में क्यों नहीं लाते है?

राव दलीप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब मैं यह कह रहा था कि किसानों के पढ़े लिखे बच्चे आज रोजगार की तला ा में घूम रहे है। हर आदमी आज कोि ा ा करता है कहीं न कहीं रि वत दे कर भर्ती हो जाये या कोई अन्य नौकरी पा ले।

चौधरी हरस्वरूप बूराः आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। राव साहबन ने यहां पर कहा कि सीलिंग एक्ट के बाद भी लोगों ने 18 एकड़ से ज्यादा जमीनें रखी हुई है। अगर सीलिंग के बाद में लोगों ने ज्यादा जमीनें रखी हुई है तो वे उनके यहां हाउस में नाम बताये।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब अभी रामकि ान जी ने हाउस में कहा कि कोई रि वत देता है या

लेता है तो उसके लिये सी0एम0 साहब एलान कर चुके है कि पकडवाने वाले को पांच सौ रूपये इनाम दिया जायेगा। अभी भागमल जी ने पचास हजार रूपये रि वत का जिक्र किया.....

श्री उपाध्यक्षः भागमल जी ने इस ढंग से कुछ नहीं कहा था। आप बैठिये।

राव दलीप सिंहः मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि किसान का बच्चा नौकरी लेने के लिये ऐम्पलाएमेंट एक्सचेंजो में घूमता फिरता है। दस–दस बारह–2 ऐक्पलाएमेंट एक्सचेंजों मे जाता है और कोि ा ा करता है कि किसी तरह से नौकरी मिल जाये। अगर आज किसान की हालत अच्छी हो तो इतनी परे ानी में पडने की और रि वत देने की क्या आव यकता है। आज वह ऐम्पलायेमेंट एक्सचेंज और सैक्रेटीरयट में चक्कर काट रहा है । इसलिये जैन साहब ने जो लैन्ड होल्डिंग टैक्स लगाया है वह वापिस लेना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब मेरी यह भी प्रार्थना है कि महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद, साहलावास, भिवानी और नारयणगढ़ ये बहुत ही पिछड़े हुये इलाके है लेकिन सरकार ने इन पर वही टैक्स लगाया है जो दूसरे इलाकों पर लगा है। हमारे इलाकों के साथ पहले भी ऐसी ही जयादती हूई थी। सवा छः एकड़ लैंड पर पहले भी मालिया माफ हुआ था। और अब भी ऐसा ही किया है कि जिन जमीनों में बासमती ओर कनक पैदा होती है वहां भी सवा छः

एकड पर मालिया माफ किया है और जहां पर घास भी पैदा नहीं होती हे, पिछडे हुये इलाके है , भूड जमीन है , बरानी है वहां पर भी इतनी ही जमीन पर मालिया माफ किया है। और यह जो 33 परसैंट बढाया है यह तो छः एकड से उपर वाली घटिया जमीन पर सौ परसैंट हो जायेगा। उन पिछडे हुये इलाको के साथ सरासर जयादती हैं जब भी कोई टैक्स लगे ततो वह प्रोपोर ान के हिसाब से लगे। जिनके पास अच्छी जमीन है उन पर सवा छः एकड तक का माफ किया है तो भूड जमीन पर जयादा पर माफ होना चाहियै। इस बात पर सरकार गौर करे और ऐसे इलाकों में ज्यादा जमीन पर रिलीफ दे और जो ज्यादा टैक्स बढाया हे इसको वापिस लिया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो पैसेन्जर टैक्स साढे बारह परसैंट बढाया है , मै इसका भी विरोध करता हूं । पिछले साल भी दस परसैंट बढाया था और इस साल फिर साढे बारह परसैन्ट बढा दिया। साधारण खत्री पर यह बडा भारी टैकस है। इसको वापिस लिया जाना चाहिये। इतना पैसेन्जर टैक्स और रोड टैक्स फी सीट के हिसाब से सारे भारत में कहीं भी नहीं लिया जाता है। एक बात जो इस प्रोपोजल में नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टै परजिसका बहुत भारी असर पडता है, मैं आपके जरिये नोटिस में लाना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा रोडवेज जो भी मुनाफा कमती है उसको सरकार रोड टैक्स और पैसेन्जर टैक्स के थ्रू वसूल कर लेती है और डिपार्टमेंट के पास बहुत थोडा पैसा बचता

है जिसके कारण डिपार्टमेंअ यात्रियों को पूरी सुविधायें प्रदान नही ंकर पाता है। सरकार भी उस मुनाफे की कुछ परसैंटेज ले लेकिन यात्रियों को भी तो सुविधाये दें तभी यह ठीक रहेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि कन्डक्टर और चालक का बिहेवियर ठीक नहीं होता है। इसके लिये सर्विस रूल्ज होने चाहिये ताकि सही एक ान हो सकैं दूसरी तरफ उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस भी हो सकती है। अगर कोई कन्टक्टर अच्छा काम करता है तो उसको इनाम दिया जाना चाहियै। जो अच्छे कंडक्टर्ज है या ड्राइवर्ज है, उनको इन्सैंटिव देना चाहिये। आप उनको इनाम देगें तो वे लोगों के साथ अच्छी तरह से पे ा आयेगें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कंडक्टर्ज और ड्राइवर्ज बगैरा को ट्रेंनिग दी जाये ताकि उनका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा हो। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी का मोल तो नहीं लगता अगर वह यह कह दें , आइये, श्रीमान जी बैठिये, या आईये, बैठिये। मै ंआपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यह तो सिफ उन्हे ट्रेनिंग देने की बात है। मैं आ ाा करता हूं कि सरकार इस बारे में जरूर विचार करेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये कम्पलीट प्रोहीबी ान की पालिसी अपनाते तो मैं सरकार के द्वारा लगाये गये टैकसों का भी स्वागत करता मगर ये तो पा ि ायल प्रोहीबी ान की पालिसी पर चल रहे है जिसका फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, वर्श 1977–78 में 56 लाख प्रूफ लिटर भाराब का कोटा सरकार ने दिया था ओर इस वर्श इन्होने 20 प्रति ात कट की पालिसी अपनाकर वह कोटा 46 लाख प्रूफ लीटर कर

दिया है। इससे इल्लीसिट भाराब की तादाद और ज्यादा बढ गयी है। हमारे राजस्थान के साथ लगने वाले जितने भी इलाके है, वहां पर लोगों ने भाराब की भट्टियां लगा रखी है। राजस्थान के कुछ गांव हरियाणा के बार्डर के साथ लगते है, वहां पर डिस्टिलरीज लगाई हुई है ंवहां से भाराब हरियाणा में आती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी इस पार्ियल प्रोहीबि न पालिसी सका कोइ फायदा नहीं हो रहा है। एक तो इससे क्राइम ज्यादा हो रहे है और दूसरे स्टेट एक्सचैकर को इससे बडा भारी नुक्सान हो रहा है। जैन साहब ने यह माना है कि हमें पिछले साल 5.84 करोड रूपये का घाटा इस प्रोहीबि ान पालिसी की वजह से रहा है। मैं यह कहता हूं कि यह जो आपको घाटा रहा, यह एक तो आपकी पार्ियल प्रोहीबि ान पालिसी की वजह से और दूसरे आपके डिपार्टमेंट की इनएफी ीयैन्सी की वजह से रहा है। आपके डिपार्टमेंट ने पिछले साल अलाटमेंट की जो नीति अपनाई उस वजह से आपको घाटा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कम्पलीट प्रोहीबी ान की पालिसी आनाये तो मैं ही क्या मेरा ख्याल यह है कि सारा हाउस इसका स्वागत करेगा। आपकी इस अलाटमेंट पालिसी से सरकार को तो घाटा हुआ लेकिन ठेकेदारों को फायदा हुआ है। जो बडे बडे ठेकेदार थे, पहले नारनोंद में जो ठेका 10 लाख में गया था, उसको आपने 500 यपये पर वह भाराब का ठेका दे दिया। इससे उस ठेकेदार को बडा भारी फायदा हुआ और उसने खूब पैसे बनये। (व्यवधान) सरकार को एक तो इस पालिसी से घाटा हो रहा है ओर दूसरे इससे काम

बढ रहे ह। घाटे को पूरा करने के लिये आप किसानों पर टैक्स पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो। जैन साहब ने यहां पर बतया है कि पिछले सल 5.84 करोड रूपये का घाटा हुआ है और आईन्दा 2 साल 2 करोड रूपये का घाटा होने जा रहा है मै ंउनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आनेवाले साल में दो करोड रूपये का घाटा होने जा रहा हैं अब इन्होने पालिसी चेन्ज की है ओर अलाटमेंट से फिर औक ान कर रहे है इस वजह से गुडगांव से 12 लाख, जमुना जगर और जगाधरी में 45–45 लाख रूपये के ठेके नीलाम हुये हैं इस तरह से एक करोड रूपया इन तीन ठेकों से ही आ गया है। मेरे पास तीन डिस्ट्रिक्टस की फिगर्ज है। उससे मुझे यह पता लगा है कि इनकी 6.22 करोड रूपये की औक ान इन तीन डिस्ट्रिक्टस में हुई है। आप देखिये हरियाणा में कुल 10 डिस्ट्रिक्टस है। जब 3 डिस्ट्रिक्टस में इतनी इन्कम हुइ है तो बाकी 7 डिस्ट्रिक्टस से जो इन्कम होगी, उसके बारे में आप अन्दाजा खुद ही लगा सकते हैं इस तरह से हमारी आमदनी 20 कराड रूपये के लगभग आती है। इसके अलावा इस भाराब पर डयूटी भी लगेगी। 1977–78 में जो आपकी इन्कम हुई थी, उसके मुकाबले में आपकी इन्कम 1979–80 में 5 करोड रूपये कम होने का अनुमान हैं यह घाटा आपकी प्रोहीबि ान पालिसी की वजह से है। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि राजस्थान का बोर्डर एकदम सील करके कम्पलीट प्रोहिबि ान की जाये ।तब तो इसका फायदा होगा वरना अगर आप पा र्ियल प्रोहीबि ान करेगें तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे उल्टे क्राइम ही बढेंगे और डिस्टिलरीज

में इल्लीसिंट लिकर निकाली जायेगी और उल्टे एक्सचैकर को नुकसान उठाना पडेगा। मेरा विचार यह है कि अगर आप इस डिपार्टमेंट को खाली टोन अप कर लें तो इससे ही आपको काफी आमदनी हो सकती है। क्म्पलीट प्रोहीबि ान करने के लिये तो आप तैयार नहीं है (व्यवघान)। जैन साहब ने जो यह टैक्स लगाये है, मै इनका स्वागत करता अगर यह क्लास फौर एम्पलाईज को कुछ रिलीफ देते। डिप्टी स्पीकर साहब, लोकल बोडीज में एक भंगी जो सफाई का काम करता है और उस काम को करने के लिये कोइ भी तैयार नहीं है, अगर ये उसको कुछ रिलीफ देते तो मैं इन्होन जितने भी टैक्सलगाये है , इनका स्वागत करता। या अगर यह जो 290000 लोग है जो बेकार है, अनएम्पलायड है, उनको कुछ अलाउन्स देते तो भी मैं इनकी टैक्स प्रोपोजल्ज का स्वागत करता। केरल के अन्दर जहां पर कि सबसे ज्यादा लिटरेसी है, यह अलांउस उन्होने दे दिया है, बैस्ट बंगाल ने दे दिया है और पंजाब ने भी मेरे विचार में अनाउन्स कर दिया है। मुझे पक्का पता नहीं उन्होने दिया है या नहीं दिया हं आप यह देखे कि जो गांव में पढे लिखे लोग है, उनका दिमाग गलत कामों की तरफ चलता है ंआपको पता ही है खाली दिमाग भौतान का घर, वाली बात हो रही है। गांवों में पढ़े–लिखे लोगों की विचारधारा गलत कामों की तरफ चल रही है। वे यह कहते है कि हमने भी तो पेट भरना है। इस तरह से तो कोई नैक्सलाईट बन जायेगा या कोई डाकू बन जायेगा। अगर हमने इस समाज को बचाना है और इस स्टैट को बरबादी से बचाना है तो मैं जैन साहब से यह प्रार्थना

करूंगा कि जो ि ाक्षित लोग है, या तो डनहे रोजगार दें वरना उन्हे अनएम्पलायमैंट अलाउन्स जरूर दें हमारे यहां 9 हजार के लगीाग ऐसे व्यक्ति है जो अन्धे है, लगंडे है या बहरे है, या डिस–ऐब्लड है जोकि रोजगार की तला ा में भटक रहे है। उनको भी आज रोजगार नहीं मिल रहा है। आप यकीन मानिये, जैन साहब को मैं यह बताना चाहता हूं कि हो सकता है उन्हे भी उन लोगों को रोजगार के लिये भटकते हुयें देखकर भार्म आती हो, मुझे तो आती है। आप देखिये वे लोग जो समाज में अपने पैरो पर खडे होना चाहते है, समाज उनकी मदद नहीं कर सकता। वे लोग बेचारे रोजगार की तला ा में भटकते फिरते है। स्टैट उनकी मदद करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम ऐसे लोगों को तो रोजगार अव य दे। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने किसानो को कुछ ब्याज में रहत दी है जो कि 14 प्रति ात से घटाकर 11 प्रति ात कर दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह जो राहत दी है, मैं यह समझता हूं कि यह ठीक किया गया है। यह सिर्फ भाार्ट टर्म लोन के लिये राहत दी गयी है, मैं यह समझता हूं कि यह ठीक किया गया है। यह सिर्फ भाार्ट टर्म लोन के लिये राहत दी गयी है, मै यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसे मीडियम टर्म लोन्ज तक एक्सटैंड कर दिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत एक और प्रार्थना करना चाहता हूं । महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिये जितना हिस्सा बजट में रखा गया है, वह मैं यह समझ रहा हूं कि उतना

नहीं रखा गया है जितना इसको मिलना चाहिये था । डेरी डिवैल्पमेंट के बारे में मिल्क प्लान्ट कई डिस्ट्रिक्ट में लगे हुये है और बल्लभगढ़ में लगाने जा रहे है। हमारा डिस्ट्रिक्ट डैजर्ट प्रोन एरिया है, बारानी इलाका है, वहां पर भैंस पालने से तभी लोगों को फायदा हो सकता है जब कि वहां पर भी एक मिल्क प्लांट हो । इसलिये मेरी सबमि ान यह है कि वहां पर भी एक मिल्क प्लांट अव य बनायाजाना चाहिये। हमारे महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ जो

भेदभाव बरता जा रहा है, वह उचित नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार का इस बात के लिये तो भ्रुकगुजार हूं कि कुछ स्कीमें हमारे यहां पर भी सरकार चलाने का विचार रखती है। एक बात मैं आपके द्वारा और सरकारसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जवाहर लाल नेहरू कैनाल के तीन–चार सर्किल है। हमारे सर्किलों के हैडक्वार्टर रोहतक में वाक्या है। मैं आपकी मार्फत आई0पी0एम0 साहब से ओर जैन साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे लोगों को कोई भी काम हो, रोहतक में जाना पडता है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। एक किसान के साथ लैंड के मुआवजे के सिलसिले में मुझे रोहतक जाना पडा। पहले तो हमें वह दफतर का ही पता नहीं चला। आखिर किसी ने हमें यह बताया कि वह दफतर आई0टी आई0 के पास है। हम घंटा भर चक्कर लगाने के बाद एस0ई0 के आफिस में पहुंचे तो वहां पर यह पता लगा कि एस0ई0 साहब टूर पर गये हूये है। समझ नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगझ़ का एस0ई0 रोहतक में क्यों बैइा

रखा है। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते है तो उसको महेन्द्रगढ़ में बिठा दें। ऐसा करने से किसानों की परे ानी बच जायेगी।

श्री उपाध्यक्षः यह आप इरिगे ान मिनिस्टर साहब को नोट करवा दे।

रावदलीप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फिर अपनी बात को दोहरा देता हूं। एस0सी0 का आफिस रोहतक मे हैं । जब लोग कम्पनसे न के लिये वहां जाते है तो बडी परे ानी होती है। मैंने एक इंस्टांस बताई है कि एक बार मैं एक किसान को लेकर रोहतक गया तो बडी मु कल के बाद मुझे आफिस मिला और फिर पता लगा कि एस0सी0 टूर पर गयाहुआ हैं आप खुद सोच सकते है कि इससे लोगों को कितनी परे ानी होतीहै। मेरी सरकार से एक और प्रार्थना है कि हिसार के अन्दर एच0एस0इ0बी0 की कालोनी बना रहे है। अगर महेनद्रगढ़ या नारनौल मे भी एक कैनाल कालोनी बना दी जाये तो अच्छा रहेगा और वहां पर अफसरों के रहने के लिये भी मकान बना दिये जाये ंतो ठीक रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, नहरों के लिये जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की गई थी आज उसको तीन चार साल हो गये है लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनको जल्दी मुआवजा दिया जायेगा।

अब मैं ला एडं आर्डर की बात कहना चाहता हूं कि गांव कनीना में पांच आदमियों का मर्डर हुआ। वे एक ही फैमिली के पांच मैंबर थे। एक आदमी, एक औरत ओर तीन जवान लडकियां । बहुत ही बेरहमी से नौजवान लड़कियां ओर उनके मां बाप का कत्ल किया गया। यह दो–तीन महने पहले का किस्सा है। वैसे मुझे खु ी है कि कत्ल करने वालों का पता लग गया है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि मूलजिमान को गिरफतार किया जाये और वह जो माल लूट कर ले गये थे उसको वापिस लिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, एक सवाल के जवाब में मुझे बताया गया कि नौ हरिजन लड़कियों को उठा लिया गया और दस लड़कियां या औरतों से बलात्कार किया गया। मैने होम मिनिस्टर साहब से पूछा कि जो नौ लड़कियां उठा ली गई उनमें से कितनी बरामद की गई तो जवाब दिया गया कि यह सप्लीमेंटरी इस सवाल से पैदा नहीं होती.....

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की बातें कहकर हरिजनो को फूक देने वाली बात न करे।**********

चौधरी पीर चन्दः आन ए पवांयट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब, अभी चौधरी लाल सिंह ने कहा कि ....मैं पूछना चाहता हूं कि दस लड़कियों को कत्ल कर

दिया गया क्या वह भी उनकी मर्जी से हुआ था। इस तरह की बात करना अच्छा नहीं है।

चौधरी लाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे में तो कोर्ट ने भी फैसला यिका है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से भाादी करती है तो वह ठीक है।

श्रीमती भाान्ति देवीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। इनके भी लड़कियां है। इनको क्या अधिकार है कि बालिकाओं के बारे में इस तरह की बात करें .....(ाोर) ये बहुत ही अभद्र भाब्द है।

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन)ः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमि ान यह है कि यहां की बात बाहर जायेगी ओर यह हाउस पर बडा भारी रिफलैक ान होगा। भाई लाल सिह ने जो भाब्द कहे है उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

चौधरी लाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैने बुरे भाब्द नही कहे है अगर डा0मंगल सैन जी को बुरे लगे है तो मैं वापिस ले लेता हूं (ाोर)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो मैने बात कही है इस बात को ये ऐप्रीि ायट करें और साथ ही अगर मगर न डालें मेरी प्रार्थना है कि उस बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः वैसे तो उन्होने अपने भाब्द वापिस ले लिये है लेकिन फिर भी ये भाब्द एक्सपंज कर दिये जायें।

राव दलीप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन लड़कियों का भगाना बडा भारी जूर्म है। और होम मिनिस्टर को बताना चाहिये कि कितनी लडकियां बरामद हो चुकी है। अभी पिछले दिनों हमारे यहां अकोदा में सड़क रोक कर तीन चार डकैतियां डाली गई थी। डाकुओं ने सडक रोक लिया था और आने जाने वाले ट्रकों को लूटा था। यह एक ही रात की बात है। वहां पर एक औरत को भी लूट लिया था और उसके सारे जेवर छीन लिये थे। मेरी आपकी मारफत होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि वहां पर पुलिस का अच्छी तरह से इंतजाम करें जिससे कि भविश्य में ऐसी वारदात न हों । उपाध्यक्ष महोदय, फर्टीलाइजर की बाब बडी भारी ि ाकायत हैं फर्टीलाइजर या तो कम होता है या मिलता ही नहीं है। मेरी यह इंफरमे ान है कि नारनौल से सारे का सारा फर्टीलाइजर ब्लैक में राजस्थान में ले जाकर बेचा गया हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

चौधरी गंगा राम (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो बजट पे ा किया गया है उसके बारे में मै ंअपने विचार रखने के लिये सबसे पहले उस आइटम को लेता हूं जिसके बारे में मैने क्वे चन आवर में ही कहा था कि हरियाणा में किसान से जो वाटर रेट चार्ज किया जाता है वह गल्त ढंग से वसूल किया

जाता है यानि किसी खेत में अगर थोडा सा भी पानी लग जाता है, पन्द्रह किल्ले में एक बूंद भी लग जाता है। तो उस किसान से पूरे पन्द्रह किल्ले का वाटर टेक्स लिया जाता है और किसान की बदकिस्मती यह है कि इस बजट के अन्दर उन वाटर रेटस के उपर और सरचार्ज लगा दिया गया हैं मैं कहना चाहता हूं किसान के उपर किसी किस्म का टैक्स लगाना बहुत गलत बात है । कुदरत तो किसान के उपर अपने आप टैक्स लगा देती है कई बार फलड आ जाता है। अगर फलड नहीं आता तो ओले पड़ जाते है, अगर ओले नहीं पडते तो टिड्डी आ जाती है और अगर टिड्डी नहीं आती तो किसी और तरह के कीड़े फसल को खा जाते है। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान के घर जितनी उपज आनी चाहिये उसका सिर्फ पांच–दस परसैंट की पहुंचती है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर कोई सारे हिन्दुस्तान का पेट भरता है , अगर कोइ हिन्दुस्तान को रोजगार देता है। अगर कोई सारे हिन्दुस्तान का पेट भरता है, अगर कोइ हिन्दुस्तान को रोजगार देता, अगर कोई सारे हिन्दुस्तान को चलाने वाला है तो वह केवल किसान और मजदूर है लेकिन बदकिस्मती यह है कि जो दे ा को लूट रहे है जो दे ा को खा रहे है , जो दे ा को बरबाद कर रहे है, जो स्मगंलिग कर रहे है, जो डाका डालते है, जो चोरी करते है, जो ब्लैक करते है, जो चारे बाजारी करते है, जो मुनाफा कमाते है ओर जो पिछले तीस साल से सारे देहात को खाते रहे है उन पर कोई टैक्स लगाने की जुर्रत नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं कि आज लोगों ने इतने आली ान, एयर कंडी ांड सिनेमा खडे

किये हुये है लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं है। देहात का कोई आदमी सिनेमा नहीं देखता। इसके अलावा भाराब की आम नीलामी करके वसूल कर सकती है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि सरकार सारे टैक्स छोड दे खाली भाराब पर टैक्स लगा दे, सारी कमी पूरी हो जायेगी। सरकार को आली ान होटलों, सिनेमा घरों, हैवी इंडस्ट्रीज और बडी–2 बिल्डिगों पर टैक्स लगाना चाहिये। आज आप भाहरों में जाकर देखें एक–एक आदमी के पास पन्द्रह–पन्द्रह एकड़ जमीन पडी हुये है ओर करोडो रूपये में वह उसको बेच रहा है। एक–एक आदमी के पास पन्द्रह–2 मन्जिल बिल्डिंग है लेकिन किसी ने अर्बन प्रापर्टी के उपर कोई टैक्स नहीं लगाया है। खाली किसान और देहात के लोगों के उपर टैक्स लगाया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार किसान के लिये काम नहीं कर रही है, देहात के लिये काम नहीं कर रही है। मैं यह मानता हूं कि देहात में पैसा लगाया जा रहा है लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी पहले ही मरा हूआ है जिस आदमी के पास खाने के लिये कोई चीज नहीं है, जिस आदमी के अपने बच्चे पढ नहीं सकते, जो आदमी अपने बच्चों के लिये कपउे नहीं खरीद सकता, जिसक `पावं में जूते नहीं है, कजनको खाने को अनाज नहीं है उन पर आज टैक्स लगाया जा रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि ऐसा करके हम बहूत गलत बात कर रहे है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वाटर रेटस पर जो सरचार्ज लगाया हुआ है, उसको खत्म किया जाये। इससे आगे मै जमीन की बात कहूंगा।

मैं 15,18,25 और 30 एकड़ की बात नहीं करता। आज अगर हरियाणा का एक किसान अपनी जमीन की बांटी अपने लडके और लडकियों में करना चाहे तो सारे हरियाणा में मु कल से दो परसैंट किसान आपको ऐसे मिलेगे जिनके पास 5 एकड से उपर जमीन नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को सभी देहाती भाईयों के भले की ही सोचनी चाहिये और किसान का भला करना चाहिये, किसान को उपर उठाना चाहिये, इससे दे ा उपर उठेगा। मै यह दावे साथ कह सकता हूं कि अगर दे ा का किसान उपर नहीं उठेगा तो हैवी इंडस्ट्रीज भी उपर नहीं उठ सकेगी, दे ा उननति के राह पर नहीं पहुंच सकेगा। इसलिये किसान की खु ाहाली के लिये, किसान की भलाई के लिये सरकार को हर तरह की रियायतें देनी चाहिये जिससे कि किसान खु ाहाल हो और खु ाहाल होकर अनाज का उत्पादन बढाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह बताना आव यकता समझता हूं कि हिनदुस्तान के अनद जितनी तिजारत है, जितने कारखाने है जितनी मिलें है , उन सब का बीमा हुआ होता है ओर जो बिरला 865 करोड रूपये की सम्पति का मालिक है, अगर उसके कारखाने के अन्दर आग लग जाये और उसका अरबों रूपये का नुकसान हो जाए तो सरकार उसका हरजाना पूरा करती है और अगर किसी बडे सरमाये दार या मिल मालिक की पैदावार में किसी प्रकार का घाटा पडता है, भाव कम होता है तो फिर भी सरकार उसक `नुकसान को अपनी जेब से पूरा करती है लेकिन किसानों के नुकसान के लिये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है।

इसलिये मैं कहूंगा कि किसानो की फसलों का भी बीमा होना चाहिये। कई भाई यह भी कहते है कि बीमा होना मु कल है पर मुझे वे भाई बतलायें कि क्या किसी ने इस चीज को अमीजामा पहनाने की कभी को ा ा की हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, अभी बाढ़ के कारण लोगों का बडा भारी नुकसान हुआ, अगर हमारे किसान भाईयों की फसलों का बीमा हुआ होता तो सरकार की तरफ से उन्हे पूरे का पूरा मुआवजा मिलता और फिर वह किसान बडे जोर भाोर से और खु ा होकर अनाज पैदा करते। चौधरी देवीलाल जी ने 100 मे से 10–15 या 20 परसैंट किसान की मदद करने की को ा ा की है और कर भी रहे है लेकिन इसके साथ मेरी सरकारसे प्रार्थना है कि कमसे कम जहां पर इतना किया जा रहा है, वहां पर किमसान की फसल का बीमा करने का भी प्रबन्ध किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं भाूगर मिल की बाबत भी कुछ कहना चाहता हूं। आज यहां पर यह कहा जाता है कि चीनी सरप्लस है। मैं दावें के साथ कह सकता हूं कि जितनी चीनी हरियाणा में पैदा होती है वह पापूले ान के हिसाब से एक छटांक चीनी एक आदमी के हिस्से आती है । यहां पर यह भी कहा जाता है। कि देहातों के अन्दर, गांवों के अनदर लोगों की परचेंजिग पावर ही खत्म हो गई है। इसलिये जनता चीनी नहीं लेती और इसलिये चीनी के भंडार दिखाई देते हैं। उधर सैंटर वाले यह कहते है कि भाूगर मिले न लगाई जाये। मै ंउन्हे बता देना चाहता

हूं कि हमारे हरियाणा के अन्दर सब से ज्यादा खेती गन्ने की होती है ओर हमारे गोहाने के इलाके में तो जौ, धान, सरसों मक्की वगैरह की और भी खेती होती है। कहने का मतलब यह है कि या तो हरियाणा के होते हूये यह दलील देना कि भाूगर मिल नहीं लगनी चाहिये, यह गलत बात हैं मैं तो इस विचार का हूं कि जहां पर जयादा गन्ना पैदा हो, वहां पर भाूगर मिले अव य लगनी चाहिये ओर उसका गन्ना अच्छे भाव में बिकना चाहिये। अगर किसान की पैदावार का भाव गिरता है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे समूचे दे ा की, हमारे हरियाणा प्रान्त की बदकिस्मती है। डिप्टी स्पीकर साहब, हम दूसरे दे ाों के अन्दर जात है, वाहं पर हम देखते है कि किसानों को हर तरह की सहूलियतें दी जाती है, वहां किसान की पैदावार का भाव गिरने नहीं दिया जाता, चाहे फसल कहीं जाये, चाहे समुन्द्र में जाये, फिर भी सरकार उसको उसकी फसल का पूरापैसा देती है तभी वे किसन जा ा से पैदावार बढाते है, जिसके कारण वे खु ाहाल है। मैं तो यह भी कहूगां कि आगर गेहूं का, गुड का, सरसों का, ओर कपास का भाव कम होजाता है तो य किसन के उपर कुल्हाड़े का काम करता है। अतः मेरी अपनी सरकार से प्रार्थना है कि वह भी दूसरे दे ाो की तरह अपने किसानों का पूरी तरह से ख्याल रखे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक बात ओर बताना चाहता हूं कि आज हमारा दे ा 75 खनदानों के हाथो में है। उन खादानों के हाथो में दे ा की सारी सम्पति है, अगर उन की सारी

सम्पति का बंटवारा कर दिया जाए , ने ानलाईज कर दिया जाए तो आज जनता के उपर टैक्स लगाने की जरूरत ही न पडे और सब को बराबर अधिकार मिल जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी सरकार का धन्यवादी हूं कि उसने अपनी बजट स्पीच में बताया है कि उसने देहाती भाईयों को उपर उठाने की पूरी कोि ा ा की है और कर भी रही है। बाढ़ की रोकथाम के लिये ड्रेनज के बारे काफी काम हो रहा हैं 138 करोड़ रूपया सरकार ने फल्ड कार्यो पर खर्च करने के लिये रखा है ओर जितनी सड़कें और डिग्गियां इस समय बनाई जा रही है, उतनी आज से पहले किसी भी सरकार ने नहीं बनाई थीं यह एक बड़ा सराहनीय कदम है लेकिन साथ–साथ हमें यह भी `दखना चाहिये कि किसान की जो मजबूरियां है, उनको किस प्रकार दूर किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक ट्रैक्टर को ही ले लीजिये, जिसको किसान चलाता है उसको किसान ही खरीदता है, और यह किसान की जान है लेकिन इन की जितनी भी सेल्ज एंजैसियां है, वे सभी सरमायेदारों के हाथों में दे रखी है और जब किसान भाई वहां पर ट्रैक्टर लेने के लिये जाते है तो उनको ब्लैक में दिया जाता है। जब लैन्ड मार्गेज बैंक से ट्युबवैल्ज वग।रह के लिये लोन लिया जाता है तब भी किसानों को ब्लैक मेल किया जाता है, इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सभी एजेंसियों को सम्भालें। डिप्टी स्पीकर साहब, खाद की एजैंसियां, कीड़े मारने वाली

दवाइयों की एजैंसियां आज सभी सरमायेदारों के हाथों में है ओर वे किसानो ंके साथ खिलवाड़ करते हे, बलैक मेल करते है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज एक किसान की लड़की की भाादी होती है तो भाादी के लिये जो भी सामान गेहूं, तेल, सरसा ै, चीनी सब्जी और ूदसरी जो भी जरूरत की चीजें है, वह किसान के लगभग गांव से 14–15 मील के फासले पर जाकर लानी पडती है क्योकि इन सभी जरूरत की चीजों की एजैंसियां सरमायेदार लोगों को दे रखी है और वे किसानों से काफी पैसा बटोरते है, इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि जो–जो चीजें किसानों की आव यकता की है, वे सभी देहातों के अन्दर ही प्रोवाईड होनी चाहिये ताकि किसानों को इतनी दूर जाकर परे ाान न होना पड़े। इससे आगे एक और बात है कि जो लोग मण्डी में बैठते है, वे भी किसानों को बूरी तरह से लूट रहे है, किसान बेचारा तो अपना सामान मंडियों में बेचने के लिये ले जाता है और वहां पर बैठे हुये सरमायेदार एक बोरी के पीछे पांच रूपये बटोर लेते है इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः गंगा राम जी, इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने आर्डर कर दिया है अब यह सारा काम पंचायतों के द्वारा ही होगा।

चौधरी गंगा रामः मुझे बडी खु ी है कि ऐसे आर्डर कर दिये है लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि बाकी जितनी किसानों

से संबंधित एजैंसियां है वह भी किसानों की मार्फत दी जानी चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात ओर कहना चाहता हूं कि आज सब लोग देहातों का काम करवाना चाहते है। जैसे आज एक रजवाहे का प्लान बनता है, ड्रेन का, मोरी लगाने का, या सड़क बनाने का प्लान बनता है तोउसको एस0डी0ओ0 भी पास कर देता है, एक्सीयन भी पास कर देता है, एस0ई0 भी पास कर देता हूं और जिस गांव से वह प्लान संबंधित होता है उस गांव के सौ फीसदी लोग भी उस को पास कर देते है लेकिन जब वह फाइल सैक्रेटिरियेट ने हमारे आई0ए0एस0 आफिसर्ज के पास आ जाती है जिन्होने कभी फील्ड देखा ही हनीं वे उस प्लान को रिजैक्ट कर देते हैं यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज हमारी सरकार की तो काम करने की नियत है लेकिन जब तक ब्योराकेसी में सुधार नहीं होगा तब तक सरकार इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी। आज ऐसे जारों केस पडे है जिन्हे लोग चाहते है कि पास हो जाने चाहिये और नीचे के अफसर भी यही चाहते है लेकिन उपर के अफसर नहीं होने देते। आज हरियाणा में कुछ रि वत बन्द हुई है लेकिन जिन अफसरों का जनता से सीधा ताल्लूक है उनकी बन्द हो गई है और जो यहां बैठे हुये है उनका हाल यह है कि एक एक फाइल को चलाने के लिये नो–नौ और दस–दस महीने लग जाते है। एक बात और देखें कि जितने हमारे मुलाजिम है उनमें से अगर फरीदाबाद में बैठा मुलाजिम कोई गड़बड़ कर दे तो उसे सजा देने के लिये हिसार ट्रांसफर किया जा सकता है और अगर हिसार में बैठकर कोई गडबड करता है तो उसे पानीपत में

ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन सैक्रेटिरियेट में जितने मुलाजिम बैठे है उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट यहां बैठै हुये है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सैक्रेटेरियेट में बैठ कर बदमा ी करे उसको नारनौल या भिवानी भेज देना चाहिये ताकि उनका भी दिमाग ठीक हो जाये। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता मैं तो स्टैट की भलाई के लिये जनरल बात कह रहा हूं।

डा0 बृज मोहनः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इन्होनें जो सैक्रेटैरियेट के बारे में बदमा ाी के लफज कहे है ये इनको वापिस लेने चाहिये।

चौधरी गंगा रामः ठीक है जी, मैं इन भाबदों को वापिस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आदमी को पता है कि मेरी कुर्सी यही रहेगी तो यह जिम्मेदारी से काम नही करेगा..... .....

राव दलीप सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। इन्होने अभी कहा ऐसे आदमी का नारनौल या भिवानी भेज दिया जाये। क्या ये नारनौल या भिवानी को जेल समझते है। (हंसी)

चौधरी गंगा रामः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि रि वत ओर बेईमान को किस तरह से बन्द यिका जाये। इसकों बन्द करने के लिये हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पडेगा और हमे

ंसख्त होना पडेगा। आज जो अफसर साहेबान की प्रोमो ान हो रही है वह ठीक है जैसे एक सिपाही से किसी को हवलदार प्रोमोट किया जाता है, हवलदार से थानेदार, थानेदार से इन्सपैक्टर और इन्सपैक्टर से डी0एस0पी0। यह बहुत अच्छा तरीका है क्योकि इस तरह से आदमी को सारी जिन्दमी तजूर्बा हो जाता हैै और वह अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता हैं लेकिन आज क्या हो रहा है कि जितने भी अफसर भर्ती किये जाती है वे डायरैक्ट भर्ती किये जाते है और डायरैक्ट आने की वजी से उन अफसरों का अनुभव नहीं होता। उनकी नीति यह बनी हुई है कि वे आफिसर को छोड़ना नही चाहते ओर असली जो काम है वहां पर जाना नहीं चाहते। तो मैं यह चाहूंगा कि कम से कम 70 प्रति ात अफसर तो प्रोमो ान के जरिये आने चाहिये ओर 30 प्रति ात डायरैक्ट आ सकते है। अब अगर कोई अफसर डायरैक्टली तौर पर ड्रेनेज डिपार्टमैंट में आ जाता है। या नहर के महकमें मे या बिजली के महकमें मं आ जाता है तो वह तो वहां पर बैठ कर अफसर ाही करेगा क्योकि उसके पास काम करने का तजूर्बा नहीं है। हमारे जो बहुत से काम रह जाते है वह इसी कम तजूर्बे की वजह से रह जाते है।

इसके बाद मैं टैक्सों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि सरकार का टैक्स लगाये बगैर काम नहीं चलता लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि टैक्सों में थोड़ी बहुत रियायत जरूर होनी चाहिये। यह बात मै वैसे ही नहीं कह रहा हूं। हम अभी

लोगों के पास गये थे और आठ दिन तक उनकी रय जानी। लेगों की राय यह है कि जब तक खेती बढाने के प्रोग्राम में हम आगे चलना चाहते है ओर कुदरत हमारे खिलाफ चल रही है तो ऐसे समय पर मजदूर किसानों के उपर टैक्सों का बोझा नहीं पडना चाहिये। आज हर आदमी को फील्ड के अन्दर जाना चाहिये ताकि हम देहाती भाइयों को समझा सकें आज कुछ हमारे दु मन ऐसे बैठे हुये है जो जात–पात के नाम का जहरीला प्रचार कर रहे है। सरकार को इस तरफ ध्यान देनाचाहिये ।हम तो एक चीज को मान कर चलते है कि हम 80 प्रति ात लोग जो खेती करते है वे चाहे हरिजन है चाहे किसान है और चाहे बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते है ये सारे के सारे एक है। कई बार भावुकता में आकर जा–पात का सवाल उठा कर लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते है। इन चीजों को रोकने के कलये यह जरूरी है कि इस बारे में भी प्रचार किया जाये औरदेहात मे आपस में मेल–मिलाप की बात चलानी चाहिये। इसके अलाव एक बात और है कि हम जो किसानों को या देहाजियों को कर्जा देते है, यह बात ठीक है कि उस पर बयाज की दर 14प्रति ात से घटाकर 11 प्रति ात कर दी है लेकिन जो बहुत बडी इंडस्ट्रीज है.....

चौधरी पीर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसे ये भाई बोल रहे है क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि इनकी भावना देहात और भाहर को अलग–अलग करने की है?

चौधरी गंगा रामः मैं जिन्दगी भर कभी भाहर के हक में नहीं रहा हू। भाहर से मेरा मतलब केवल 15 प्रति त आदमियों से है जो आराम की जिन्दगी बसर करते है, भोग विलास करते हे और करोडो रूपये के मालिक है। चाहे वे बम्बई में है या कलकत्ता मे है मैं तो ऐसे आदमियों के खिलाफ हूं। मैं इस प्रकार के भाहर को नहीं देखना चाहता बल्कि मैं तो सारे हिन्दुस्तान के देहातों को भाहर के रूप में देखनाचाहता हूं।

श्री देवेन्द्र भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी कुंवारा हूं लेकिन ये एक ऐसी बात कह गये जिसकी इनको नालेज भी नहीं हैं मैं आपके द्वारा इनसे रिक्वैस्ट करता हूं कि अगर ये स्वामी जी है तो स्वामी जी रहे लेकिन ऐसे भाब्द मत कहें जो भाोभा न दें।

चौधरी गंगा रामः अगर कोई ऐसी बात मैंने कह दी है तो मैं वापिस ले लूंगा। अगर आपका इ ारा भोग की तरफ है तो अगर बहुत सरी मिठाई रख कर आप खाये ंतो उसको भी भोग कहा जाता है लेकिन अगर गन्दी पिक्चरें ओर नाच देखने जाओं तो उसे विलासिता कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी अब आप समाप्त करें।

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मै थोडा समय और लेना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमसब सदस्यों को

मालूम है कि बाबू मूलचन्द जैन जी तो बडे समावादी है, ते बडे अच्छे ख्यालों के है, वे इस प्रकार क ख्यालों के होकर मैं नहीं समझता कि किसान और मजदूर पर इतने टैक्स लगाएंगे, ऐसा लगता है कि उनके उपर तो किसी और का प्रभाव है। उनकी कलम से तो लिखवा लिया गया है। मैं जैन साहब से प्रार्थना करूंगा कि कुछ चीजों से टैक्स हटा दें जो गांव के लोगों के काम आने वाली है तो सारे देहात के लोग उनका बहुत मान करेगें, उनकी तस्वीर बनाकर पूजेंगें, उनके गलें में माला पहनाएंगें और कहेंगें कि जैन साहब ही ऐसे आदमी आये है जिन्होने किसान की आवाज को सुना है, दुखों को दूर किया है। मैं इन भाब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करते हूये बैठता हूं।

लाला बलवन्त राय तायल(हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, बजट पे ा होने से पहले हम लोगों को ख्याल था कि चूंकि यह जनता बजट है इसलिये इस बजट में कोई टैक्स नहीं लगाए जगंगे लेकिन जैन साहब ने जब यह बज टपढा तो पता लगा कि इसमें टैक्स कम करने की बजाये बढाने की तरफ ज्यादा जोर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब सदन में बज टपढा जा रहा था तो देखने में आया कि कैबिनेट रैंक के आदमियों ने बजट की कापियों को फाड़ा। यह बडी अ ोभनीय बात थी कि जो बजट सरकार पे ा करे उसी सरकार के आदमी जिन को बजट के बारे में बडी सोच समझ कर बात करनी चाहिये, वे ही बजट की कापियां फाडें। (विघन) इस बजट के अन्दर जितने भी टैक्स लगें

है, उनके बारे में चर्चा हुइ है और उस पर विचार होना भी चाहिये कि हरियाणा के अन्दर पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स है। हरियाणा में सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा टैक्स लगाये गये है। आप बराबर की ही स्टेटों को देखिये। राजस्थान में अनाज पर 1 परसैंट मार्किट फीस और 2 परसेंट सेल्ज टैक्स लगता है। परन्तु हमारे चहां तीन परसेंट मार्किट फी लगती है और 4 परसैंट सेल्ज टैक्स। ऐसी हालत में आप अन्दाजा लगा सकते है कि हमारे यहां जो एग्रो–इंडस्ट्रीज है, क्या वे यहां रह सकती है? डिप्टी स्पीकर साहब, या तो वे राजस्थान मे ंजायेगी या दिल्ली में जाएंगी, जहां पर कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ ही साथ, डिप्टी स्पीकर साहब, जब टैक्स लगाए जाते है तो एक बात का ख्याल रखा जाता है कि टैक्स लगाने से जो सरकार को आमदनी होती है, उससे पब्लिक की बहबूदी के लिये कोई काम किया जाता है या उन टैक्सों की आमदनी से सिर्फ यही काम करते है कि छोटी सी स्टैट में हमने जो हैवी एडमिनिस्ट्र ान अपने उपर लाद लियाहै, उन आफिसर्ज की तन्खाहों में ओर टी0ए0 में वे पैसे दे यिे जाएं या मिनिस्टर्ज ने जो फारेन गाडियों ले रखी है , उन गाड़ियो पर ही वे पैसे खर्च कर दिये जाये। पब्लिक की बहबूदी पर अगर वह पैसा खर्च नहीं किया जाता और दूसरी चीजों पर ही खर्च कर दिया जाता है तो यह बडी गलत बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, टैक्सों के लगाने के साथ–2 जब हम देखते है कि इन्होने लोगों को कितनी राहत दी है, यह तो बजट को पढने से पला चलता है कि सरकार द्वारा राहत के लिये कोई भी काम नहीं किया गया, सिवाये चन्द ऐसी

बातों के, जैसे कि इन्होने एक लख तक सेल्ज टैक्स में छूट दी है। डिप्टी स्पीकर साहब, मै समझता हूं कि इस से गरीब दुकनदारको फायदा होगा और इसके लिये मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहब को बधाइ देना चाहता हू। लेकिन इसके साथ ही साथ हलवाइयों पर 40 हजार की बिक्री का हिसाब नहीं रख पाता हे तो वह टैक्स कैसे दे पायेगा और हिसाब न रखने की वहज से आप के इन्सपैक्टर्ज, और सेल्ज टैक्स डिपार्टमेंट वाले उन हलवाइयों को रोज तंग करेगें। इसलिये सरकार को यह सोचना चाहिय कि हलवाइयों पर टैक्स लगाया जाये या न लगाया जाये। मेरी यह प्रपोजल है कि अगर उन पर टैक्स लगाना जरूरी है तो उनकी कुछ कैटैगरीज बनादे, और जैसे सिविल सप्लाईज वाले हलवाइयों को क्लास–1, क्लस 2 और क्लास 3 की भूगर दिया करते है, उसी तरह की कोई बात कर दे तो दोनों पार्टियों को ायदा होगा। सरकार को भी कुछ पैसा मिल जाएगा और उनका भी काम चल जाएगा। अव्वल तो मैं कहूंगा कि हलवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये और अगर लगाना जरूरी है तो मैने जो प्रोपोजल दी है उस पर विचार कर लिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, लैंड टैक्स के बारे में बहुत लोग नाराज हुय है। डिप्टी स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में 18 लाख लैड होल्डर्ज है , जिनमें से 17 लाख तो ऐसे है जिनके पास सवा छः एकड़ जमीन है, बाकी रह जाते है एक लाख लोग। एक लाख आदमियो के अन्दर मेरे जैसे, आप जैसे आदमी भी है और राव

साहब जैसे आदमी भी है। हां, थोडे से आदमी और दूसरे होगे। सिर्फ एक लख आदमियों पर टैकस लगया है और फिर भी लोग नाराज हो रहे है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। अगर ये समझते है कि सवा छः एकड जमीन थोडी है तो आठ या 9 एकड पर टैक्स माफ करवा लें। लेकिन क्या आपने यह देखा है कि सरकार को लैंड टैक्स से आमदनी कितनी है? मेरे पास फिगर्ज है, लैंड टैक्स से सिर्फ 3 करोड और कुछ लाख की आमदनी होती है और 2 करोड कुछ लाख का खर्चा हैं इसमें आप सरकार को कितनी आमदनी देते है। डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर चर्चा है कि इरीगे ान पर 10 परसेंट टैक्स बढा दियां उसको विदड्रा करना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार ने पिछले बजट में भी कुछ लगाया था और बाद में विदड्रा कर लिया गयाथा। पानी पर जो टैक्स लगाया हुआ है , मैं भी मानता हूं कि वह ज्यादा है और यह नहीं होना चाहिये कि अगर पानी पर ज्यादा खर्चा आता है तो हम जितना बोझा टैक्स की भाक्ल में लोगों पर डाल सकते है, वह डालते रहे । डिप्टी स्पीकर साहब, इरीगे ान की सब स्कीमों से 11 करोड की आमदनी है जबकि इस पर 44 करोड रूपया खर्च आता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान पदासीन हूये) चेयरमैन साहब, 11 करोड की आमदनी ओर 44 करोड का खर्च होता है ओर फिर हम यह कहते हैं कि इन गरीब हलवाइयों पर टैक्स लगा दो जिन पर कोई खास खर्च नहीं किया जाता। मेरे एक भाई कहते है कि भाहर मं जो लोग रहेते है वे सभी मालदार है। रहते तो गंगा राम

भी भाहर में ही है, यह नहीं कि वे देहात मं रहते हो, । ाहर तो उन्हे भी अच्छा लगता है, लेकिन एक नारा उन्होने पकड रखा है.... .....

चौधरी गगां रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैंने यह बिलकुल नहीं का कि जो लोग भाहर में रहते है वे विलासिता से रहते है। मेरा दूसरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि मैं तायल साहब से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 44 करोड रूपया इरीगे ान काखर्च आता है, वह 10 साल में आता है या एक साल में?

लाला बलवन्त राय तायलः आपने भी बजट पढा होगा , यह एक साल में खर्च किया जाता है। चेयरमैन साहब, मैं टैक्स के बारे में जिक्र कर रहा था कि इधर पानी पर टैक्स लगाने के बारे में काफी भाोर हुआ, उधर लैंड होल्डिंग पर टैक्स लगाने पर भाोर हुआ। अब सरकार को सोचना है कि वह टैक्स लगाए या न लगाए। यह सरकार की मर्जी है, लेकिन अगर कोई आदमी यह चाहे कि हरियाणा में टैक्स बढाने है तो सोर्स सिर्फ यही है। इनके इलावा और कोई सोर्स नहीं है, सिवाये इसके कि आप आदमी के चलने फिरने पर टैकस लगा दे। चेयरमैन साहब, मै आपको बताना चाहता हूं कि हिसर में काफी दाल मिले है और आज हर एक दाल मिल का मालिक, हरियाणा में दाल मिल लगाने की बजाये दिल्ली में दाल मिल लगानाचाहता है क्योकि वहां कोई सेल्ज टैकस नहीं है और न मार्किट टैक्स है। उनका व्यापार वहां खूब चलता है सभी व्यापारी वहां जाना चाहते है। इडंस्टरीज के यहां

रहने से आपके लाखों लोगों को काम मिलता है। इस तरह से टैक्स लगाकर हमारी सरकार इन लोगों को मजबूर कर रही है कि वे बाहर चले जाएं।

स्वामी आदित्यवे ा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। हमारे माननीय साथी ने अभी सदन के सामने जो 44 करोड के आंकड़े रखे है, वे ठीक नहीं है क्योकि जो 44 करोड की फिगर्ज है , यह सिंचाई नव चालन, जल–निकास, बाढ़ नियन्त्रण परियोजना, सब के लिये है, अकेले सिंचाई के लिये 44 करोड नहीं है।

लाला बलवन्त राय तायल: मैने जो 44 करोड़ की फिगर्ज बताई है, वह सारे सिंचाई विभाग की है। अगर स्वामी आदित्यवे ा समझते है कि मेरी फिगर ठीक नहीं है तो वे अपनी बात कह दे। जो फिगर्ज मुझे नजर आई, वे मैंने पढ दी है। चेयरमैन साहब, मैं हरियाणा में टैक्सिज के बारे में कहना चाहता हूं। अगर किसी आदमी को हरियाणा की कोर्ट में एक लाख रूपये का दावा करना हो तो उसको 8500 रूपये कोर्ट फीस लगानी पडती है जबकि पंजाब में 3500 रूपये और दिल्ली में भी 3500 रूपये है तथा राजस्थान मेंइससे भी कम है। चेयरमैन साहब, अगर एक आदमी अपनी जायदाद की तीन–चार दफा रजिस्टरी करायेगा तो वह जायदाद तो रजिस्टरी कराने में ही सरकार की हो जायेगी। हरियाणा एक छोटी सी और हैवी एडमिनिस्टडर्ड स्टेट है ओर इसी कारण इतने टैक्स बढाये जा रहे है। चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर पुलिस में तीन आई0जी0 फुल फलैजड बना

दिये और उनमें से ऐ आदमी को तेा अम्बाला का मालिक ही बना दिया है। वह आदमी आई0जी0 भी हे और अम्बाला का डी0अई0जी0 भी है। चेयरमैन साहब, क्या एक आदमी आई0जी0 और डी0आई0जी0 रह सकता है। ऐसे काम ओर कोई नहीं कर सकता केवल यही सरकार कर सकती है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि तीन आई0जी0 के साथ–2 हमने कितेन ओर फाईनैन्ि ायल कमि नर बढाये है। उस बात के बारे में कोई नहीं सोचता कि ऐसा करने से हमारा कितना खर्च बढता हैं । एक क्वै चन के जवाब से पता लगा कि डेढ़–2 लाख रूपये टेलीफोन पर खर्चा हो जाता है। अब हमें विलायती गाड़िया भी चाहिये, चाहे हम देहात का आद र्ा रखते है, चाहे हम आद र्ा रखते है देसी चीजों का लेकिन हमं गाड़ी चाहिये विलायती। क्या हम अपने दे ा की गाड़ी नहीं ले सकते? क्या हम उस रूपये को बचा नहीं सकते? लोगों के उपर टैक्स लगाने की बजाय मैं तो जैन साहब से अर्ज करूंगा कि वह अपने साथियों के साथ सलाह म ावरा करें और यह कहें कि हरियाणा में ज्यादा टैक्स न लगाये जायें। चेयरमैन साहब, हरियाणा के अन्दर जितना टैकस हरियाणा की पब्लिक से लिया जाता है। (ाोर)

श्री दीपचन्द भाटिया: प्वायंट आफ आर्डर सर। मै ंतायल साहब से पूछना चाहता हूं कि जैन साहब हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर बन गये तो क्या वह चीफ मिनिस्टर बन गये आप कहते है कि

आप आ करके सब मिनिस्टरों से बातचीत करो अभी तोवह फाइनैंस मिनिस्टर ही है। (ोर)

श्री सभापतिः भाटिया साहब, आप बैठिये।

लाला बलवन्त राय तायलः चेयरमैन साहब, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि सदन में 90 मैंबर बैठे है इनमे से किसी ने भी ट्रांस्पोर्ट की पालिसी को स्पोर्ट नहीं किया। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि आपकी बसें ठीक नही चलती है। मुंझे भी आपकी बसों में कभी–कभी बैठने का मौका मिलता है। मैं एक दिन हिसार से चण्डीगढ़ के लिये चला। हिसर से चण्डीगढ बस को आने में 6 घंटे लगते है लेकिन वह बस 11 घंटे में पहुंची आपकी ऐसी बसें चल रही है। हमारे एक ऐलनाबाद के एम0एल0ए0 ने कहा कि बसों के अन्दर सीधे घुस जाओ खिडकी खोलने की जरूरत नहीं कयोकि खिड़कियां तो है ही नहीं यह हालत है आपकी ट्रांस्पोर्ट की और उसके बारे में कोई भी आदमी सैटिस्फाईड नहीं है। चेयरमैन साहब, अगर कोइ आदमी भाादी के लिये कोई गाडी बूक करवाने के लिये जाता है तो उसे कोई भी गाडी ठीक ढंग से नहीं मिलती अगर मिलती भी है तो वह ठीक वक्त पर नहीं पहुंचाती। इसलिये लोग बहूत तकलीफ मं है। आजकल क्या होता है कि लोग इक्ट्ठे हो करके कोई दार्जिलिंग जाना चाहता हूं कोई भारत द र्न के लिये जाना चाहता है तो कोई तीर्थ यात्रा के लिये जाना ाहता है लेकिन आपकी हरियाणा की गाड़ियों के भरोसे तो वह हरियाणा के बाहर

नहीं जा सकते। इसलिये ट्रांस्पोर्ट की पालिसी पर सरकार को दोबार गौर करना होगा। इस पालिसी के बारे में मैं सरकार को एक सजै ान दूंगा अगर वह मुनासिब समझे तो उस बात को मान ले। जैसे दिल्ली के अन्दर है उसी प्रकर हरियाणा में कर दियाजाए। आप बसिज को चलाने का काम कोआप्रेटिव सोसाइटी को दे`द और चाहे उन नौजवानों को दे दे जो बी0ए0 एम0ए0 पास करके बेकार है मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली में कुछ आदमियों को इजाजत है कि वह बसों को भाादी, भारत द र्ान और तीर्थ यात्रा के लिये ले जा सकते है। हरियाणा में भी यह इजाजत होनी चहिये ताकि लोगों को तकलीफ न हो। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा में ला एंड आर्डर की हालत अच्छी नही है। हिसार से जो सडक राजगढ जाती है उस सडक पर सिवानी और झुम्पा गांव आते हैं वहां पर आज से 15–20 दिन पहले दो डाकुओं ने 150 ट्रक रोक लिये और उन्होने ड्राईवरों, जो कि अउपने आपको बहुत होि ायार समझते है उनकी भी तला ी ले ली ओर उनके पास घडिया और जो पैसे थे वह सब निकलवा लिये। उनका आज तक कोई पता नही ओर न ही उनके बार` में कुछ हुआ है। चेयरमैन साहब, आपने देखा होगा कि जो डाकू दिल्ली में मारा गया है जिसने भाहबाद के पास डाका डाला था और भी कई जगह डाके डाले और वह हरियाणा तथा चण्डीगढ में काफी अर्से तक घूमता रहा लेकिन उसको हरियाणा की पुलिस नहीं पकड सकी। दिल्ली की पुलिस ने उसको पकड कर मार दिया। हरियाणा की पुलिस तो किसी आदमी के कसे भी रजिस्टर

नहीं करती अगर करती भी है तो उनकी इन्कवायरी नहीं होती है। हरियाणा मे कितनी चोरयिा होती है , कितने डाके डलते है और कितने ही कत्ल होते है लेकिन उनकी गिनती कम दिखाई जाती है। यह आपके ला एंड आर्डर की हालत है। हरियाणा के लोग आज ला एंड आर्डर की हालत से सैटिस्फाईड नहीं है ओर लोगों का सैटिस्फाईड न होना यह किसी भी सरकार के लिये ठीक नहीं है। सरकार को उसके उपर पूरा ध्यान देना चाहिये। चेयरमैन साहब, मै एक बात इरीगे ान के बारे में कहना चाहता हूं कि जब हम सतलूज ब्यास के पानी का जिक हाउस के अन्दर करते हे तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे पहले तो भाायद चौधरी बसी लाल जी की उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से लडाई रहा करती थी लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी की तो अब पंजाब के मुख्य मंत्री जी से दोस्ती है। हमारे होम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि कुछ दिन के बाद आपको लोग कस्सी से काम करते हुये मिलेंगें। पंजाब वाले वह पानी पाकिस्तान को दे सकते है लेकिन हरियाणा को वह पानी देने के लिये तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है वह हरियाणा को पानी क्यो नहीं देते? चेयरमैन साहब इसमें हरियाणा सरकार क्या कर सकती है? वह अपनी फौज ले करके लडाई तो लडेगी नहीं। वह फैसला तो सैंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में होने चाहिये थे। यह सरकार की कमजोरी है। इससे हरियाणा को नुकसान है और हस नुक्सान से हमारी इरीगे ान पर बहुत बुरा असर पडता है। आज हमारी बहुत सारी जमीन पानी न मिलने के कारण बेकार पडी है। जो रूपया हमने नहर बनाने के

अन्दर वेस्ट किया है वह किसी काम नहीं आया है। हमें सैंट्रल गवर्नमेंट इसमें कमजोरी दिखायेगी तो इससे नुकसान हरियाणा को होगा पंजाब के पास तो अपनी सब कुछ है चेयरमैन साहब, इस दुनियां में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो ताकत इस्तेमाल करने पर मिलती है। आप देखे, भाखडा से हमें 56परसैंट पानी मिलना था लेकिन वह 38 परसेंट मिल रहा है। पहले यह कहा जाता था कि हरियाणा के अन्दर लाइंलिग नहीं थी ओर बिजली की खपत नहीं थी, इसलिये नहीं दी गई ओर इस तरह पंजाब वाले 18 परसेंट बिजली और पानी खा गये। इसी तरह अब बयास का पानी नहीं देना चाहते है। सतलूज बयास लिंक के बारे में सरकार लोगो को कहती है कि हम पानी लेगें और पानी से लोगों के पेट भर देगें। चेयरमैन साहब, इसके लिये काफी जदोजहद करनी पडेगी, यह आसानी से नहीं मिलने वालाहै। जब तक हम पानी नहीं लेगे, हम डिवैल्पमेंट के काम नहीं कर सकते। पौंग डैम के बारे में पजाबं वाले कहते है कि हरियाणा का हिस्सा नहीं है। किस आधार पर कहते है? जिस वक्त हरियाणा बना था और इससे पहले जो स्कीमें ज्वाएंट पंजाब में भुरू हो चुकी थभ उन पर हरियाणा का 40 परसैंट हिस्सा बनता हैं जैसे दूसरी चीजें मिलती है उसी तरह पोंग डैम के उपर भी हमारा 40 परसैंट हिस्सा है और हम इस हिस्से को नहीं लेगें तो यह हमारी अपनी कमजोरी हैं। यह तो ठीक बात है, बडा भाई छोटे भाई के उपर जयादतियां करता आया है।

चेयरमैन साहब, सरकार ने वर्कचार्ज को 24 लाख रूपया दिया है और मैं समझता हूं कि यह बडा सराहनीय कार्य है। बहुत दिनों से एक डिसप्यूट चला आ रहा था, उनकी मांग थी कि वर्कचार्ज की ग्रिविएंसजि को दूर किया जाये। सरकार ने इनकी ग्रिविएंसिज को दूर करके बहुत अच्छा काम किया है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा एक मसला ओर है ओर वह है तबदीजियों का सरकारी मुलाजमों को ट्रांसफर करने की पालिसी बहुत खराब है। एम0एल0एज0 को सबसे ज्यादा काम या तो ट्रांसफर करवाने का है या नैकरियां दिलवाने का। अगर कहीं कोई जुल्म हो जाये , इस जुल्म कोदूर करने के लिये कोई आदमी नहीं आता। आप एम0एल0ए0 होस्टल में जा कर `दखिये, लोग ट्रांस्फर ओर नौकरियों के चक्कर में घूम रहे है। किसी को ट्रांस्फर करना मिनिस्टर के बस की बात नहीं है, सी0एम0 साहब के दफतर से ट्रांस्फर के आर्डर निकलते है। मै ंआपको सुझाव दुंगा कि जो ट्रांस्फर हम करना चाहते है वह मार्च महीने के अन्दर–2 कर दे। मार्च के बाद उसी आदमी की ट्रांस्फर की जाये जिसका बिहेवियर पब्लीक के साथअच्छा नहीं है ओर वह भी इन्कवायरी करने पर अगर साबित हो जाये तब ट्रांस्फर किया जाये। यह नहीं कि 10 आदमी मिल कर किसी के खिलाफ कह दे और उनके कहने पर आप उसको फौरन ट्रांस्फर कर दे। जब तक पूरी तरह से सैटिस्फैक ान न हो जाये कि फलां कर्मचारी की पब्लिक के साथ डीलिंग अच्छी नहीं हे तभी उसको मार्च के बाद ट्रांस्फर करना चाहिये। इसलिये जनरल ट्रांस्फर मार्च महीने में ही होनी चहिाये

ओर एक कर्मचारी 3 साल तक वहां रहना चाहियेक, जल्दी–2 ट्रांस्फर करने से स्टेट की डिवैल्पमेंट के कामों में फर्क पडता है। (व्यवधान) अगर कोई आदमी यह कहे कि तबदीली कोई सजा नहीं है यह गलत बात है , जिनकी तबदीली होती है उनके दिल से जाकर पूछिये कि सजा है या नहीं। अगर सरकारी आफिसर्ज की तबदीली कभीयहां कर दी जाये, कभी वहां कर दी जाये, इससे लोगों को बडी भारी तकलीफ होती है, उनके बच्चो की पढाई का नुकसान होता है। इस समस्या का हल सरकार को करना चाहिये, तभी आफिसर हरियाणा की डिवैलपमेंट के लिये काम कर सकेगें।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही साथ मैं प्रोहिबि न की पालिसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारें मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि पिछले सल जो प्रोहिबि ान की पालिसी थी वह ठीक नहीं थी। सब लोग यही कहा करते थे कि ठेकों को अलाट करके सरकार ने नुकसान किया है।

श्री सभापतिः मैं आपके रिक्वैस्ट करूंगा कि आप वाइंड–अप करें। 5 मिनट के अन्दर वाइन्ड–अप करे।

लाला बलवन्त राय तायलः बस एकमिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं प्रोहिबि ान की पालिसी के बारे में कह रहा था पिछली प्रोहिबि न की पालिसी ठीक नहीं थी। इस के बारे में सभी एम0एल0एज0 ने कहा था कि ठेके नीलाम होने चाहिये, अलाटमैंट नहीं होनी चाहिये क्योकि अलाटमेंट पर हर एक को

भाक होगा, स्टेट की आमदनी भी कम होगी। मुख्य मंत्री जी ने हमारी यह बात मानी और मुंझे इस बात की बडी खु ी है कि उन्होने अपनी गलती से माना। नीलामी करने से स्टेट को चाहे फायदा होता है, चाहे नुक्सान होता है, यह खास बात नहीं है, ऐसा होता है ही रहता है, लेकिन खास बात यह है कि उनहोने अपनी गलती को मान लिया है, यह उनका बड़प्पन है। मै एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन पंचायतों ने रैजोल्यु ान पास करकें भेज दिये है कि वहां ठेका नीलाम नहीं होना चाहिये , वहां नीलामी क्यों होती है? पंचायतों ने रैजोल्यू ान पास करके भेजा है कि हम नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी वहां ठेके नीलाम होते है। एक तरफ तो हम यह कहते है कि प्रोहिबि ान की वजह से चाह`आमदनी कम हो लेकिन हम प्रोहिबि ान करेगें ओर दूसरी तरफ लोगों की भावना के मुताबिक प्रोहिबि ान नहीं करते। इसलिये जिन पंचायतों ने रेजोल्यु ान भेजे है, वहां ठेके नीलाम नहीं करने चाहिये। अगर नीलाम करेगें तो बेकायदगियां बढेंगी, उल्टा नुकसान होगा। चेयरमैन साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

चौधरी राम कि ान (सफीदों): चेयरमैन साहब, मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका कदया। कल से बजट के उपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन के सामने रखें, मैं भी चन्द विचार आपके सामने

रखना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री श्री जैन साहब ने जो बजट पे ा किया है , मै ंइसका ह्रदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। जो टैक्स बढायें है इसके बारे में एक कमेटी बनी है ओर यह कमेटी इस पर पुनर्विचार करेगी। टैक्स प्रोपोजल्ज में आबियाने पर जो 33 परसैंट सरचार्ज बढाया है ओर स्टैम्प डयूटी बढाई है, इनके बारे में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन टैक्सिज को वापिस लेना चाहिये। चेयरमैन साहब, विपक्ष के सदस्य इस बात को मानते है कि जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद देहातों में कितनी तेजी से काम किया है। मेरे भाई पोहलू साहब खुद इस बात को मानते है कि इस सरकार का रवैया, 82 परसैंट जनता जो देहातों में रहती है, इसके उत्थान के लिये काफी जोरों से काम करने का रहा है। अभी सरकार को 20 महीने सत्ता में आये हुये है लेकिन इन 20 महीनों में भगवानर के प्रकोप के कारण हरियाणा का एक तिहाई हिस्सा बाढ़ की लपेट में आ गया।

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

(13.00 hours)

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 21st March, 1979)

परिि ाश्ट 'ए'

Chaupals for Harijans

***1150. Chaudhri Bhagmal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total number of chaupals for Harijans constructed during the year 1978-79 (upto 28-2-79);

(b) the total number of chaupals which are under construction at present;

(c)the total amount which has been spent by the government on the construction of chaupals as referred to in part (a) above;

(d) the total amount likely to be spent bhy the Government on the chaupals as referred in part (b) above: and

(e) whether the unspent amount out of the amount earmarked dor the construction of chaupals for the year 1978-79 will be spent by 31-3-79?

Revenue Minister (Shri Preet Singh):

(a) 195 Harijan Chaupals have been constructed upto 28-2-79.

(b) 912.

(c) Rs. 1951730.

(d) Rs. 6641370.

(e) Yes.